● वर्ष-4
● अंक-81
रायपुर, बुधवार
13 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

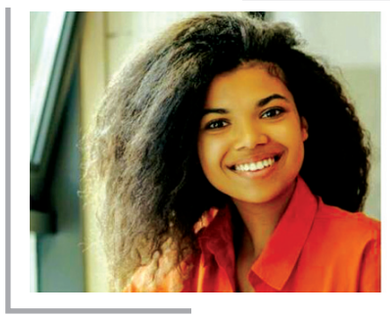

पेज-6» अब डिजिटल मार्केटिंग में पा सकते है...

खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत हुई

14 महीने में पहली बार आरबीआई के दायरे से बाहर

नई दिल्ली। अक्टूबर महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 6.21 प्रतिशत हो गई, यह पिछले महीने के 9 महीने के उच्चतम स्तर 5.49 प्रतिशत से और अधिक है। महंगाई दर में इजाफे का मुख्य कारण खाने-पीने के चीजों की बढ़ती कीमतें हैं। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 14 महीनों में पहली बार, यानी अगस्त 2023 के बाद से पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत की टॉलरेंस बैंड को पार कर गई है।

मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 6.21 प्रतिशत हो गई, जो इससे पिछले महीने 5.49 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के टॉलरेंस बैंड के ऊपरी स्तर को पार कर

गई है।

पिछले साल अक्टूबर में 4.87 फीसदी थी महंगाई दर

अक्टूबर 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4.87 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 10.87 प्रतिशत हो गई, जबकि सितम्बर में यह 9.24 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व इसी महीने में 6.61 प्रतिशत थी।

आरबीआई, जिसने इस महीने की शुरुआत में प्रमुख अल्पकालिक ऋण दर को अपरिवर्तित रखा था, को सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे।

एनएसओ ने कहा, अक्टूबर 2024 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित सालाना मुद्रास्फीति दर 6.21 प्रतिशत है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमश: 6.68 प्रतिशत और 5.62 प्रतिशत है।

सब्जियों, फलों और तेल से बढ़ी महंगाई

एनएसओ के आंकड़ों से पता चला है कि अक्टूबर 2024 के दौरान दालों, अंडे, चीनी और कन्फेक्शनरी व मसालों के उपसमूह में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। एनएसओ ने कहा, अक्टूबर 2024 में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और तेल व वसा की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ी। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि सीपीआई मुद्रास्फीति चिंताजनक रूप से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो एमपीसी की मध्यम अवधि की लक्ष्य सीमा 2-6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गई है।

दर कटौती की संभावना नहीं

उन्होंने कहा, मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों वृद्धि के कारण हुई। इसके बाद अन्य प्रमुख वस्तुओं की कीमत में मामूली वृद्धि हुई। नायर ने आगे कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के टॉलरेंज बैंड को पार कर गई है और इसके वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए एमपीसी के अनुमान से कम से कम 60-70 बीपीएस अधिक रहने की उम्मीद है, ऐसे में दिसंबर 2024 की एमपीसी बैठक में दर में कटौती की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि 50 आधार अंकों की दर कटौती का एक का सिलसिला फरवरी 2025 या उसके बाद शुरू हो सकता है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति के मोर्चे पर चिंताओं का हवाला देते हुए अक्टूर में पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा बाद प्रमुख अल्पकालिक ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा था। एनएसओ की ओर से साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर देश भर के चयनित 1,114 शहरी बाजारों और 1,181 गांवों से मूल्य आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

रायपुर दक्षिण विधानसभा में डाले जाएंगे वोट

झारखंड में पहला चरण आज

रायपुर/रांची। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल बुधवार को मतदान होगा। सुबह 7.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। पुलिस की गश्त व निर्वाचन आयोग की पैनी नजर लगी हुई है। वहीं चुनाव लडने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी पर पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर दक्षिण के 2 लाख 71 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

वहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए मंच तैयार है, जब 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता मतदान के लिए जाएंगे। मैदान में 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी क्योंकि मतदाता इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपने नए विधायक चुनेंगे। 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 17 सामान्य सीटें, 20 अनुसूचित जनजाति के लिए और छह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जिन प्रमुख नामों की किस्मत अधर में लटकी हुई है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को थम गया। बुधवार को जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उनमें पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक 6 सीटें हैं, इसके बाद पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिलों में 5-5 सीटें हैं, जबकि कोडरमा और रामगढ़ जिलों में 1-1 सीट है।

पहले चरण में सरायकेला, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर पूर्व शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह झारखंड चुनाव से पहले अगस्त में भाजपा में शामिल हुए थे। जमशेदपुर पश्चिम में स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता का मुकाबला जदयू नेता सरयू राय से है, जिन्होंने 2019 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास को हराया था। जमशेदपुर पूर्व में कांग्रेस उम्मीदवार अजॉय कुमार का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू और भाजपा की पूर्णिमा दास से होगा। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर में कांग्रेस के सोना राम सिंकू के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। रांची सीट पर लंबे समय से बीजेपी विधायक रहे सीपी सिंह का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता और मौजूदा राज्यसभा सांसद महुआ माजी से है। राज्य भर में स्थापित 15,344 मतदान केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था के बीच 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा।

जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर

रायपुर। जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय, जनभागीदारी पहल के तहत जल संचय के एक लाख 53 हजार 533 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 10 हजार 872 कार्य प्रगतिरत हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है।

छत्तीसगढ़ में जनभागीदारी से जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, जहां 35 हजार 758 जल संचय के कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 5064 कार्य प्रगतिरत हैं। दूसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहां 16,389 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 1643 कार्य

प्रगति पर हैं। तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है, जहां 16,629 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 662 कार्य प्रगति पर हैं। चौथे स्थान पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला है, जहां 16,730 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 300 कार्य प्रगति पर हैं। पांचवे स्थान बलरामपुर-रामानुजगंज जिला है, जहां 8618 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 586 कार्य प्रगति पर हैं। छठवें स्थान पर गरियाबंद जिला है, जहां 6899 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 634 कार्य प्रगति पर हैं। सातवें स्थान पर दुर्ग जिला है, जहां 4915 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 609 कार्य प्रगति पर हैं। दसवें स्थान पर धमतरी जिला है, जहां 3706 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 107 कार्य प्रगति पर हैं।

गौरतलब है कि जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है। यह पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सामूहिक पहल एवं एकजुटता से जलसंरक्षण की संकल्पना को साकार करती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अन्य गतिविधियों के अलावा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रमुख समाचार

जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील जाएंगे मोदी

नई दिल्ली। इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। रियो-डि- जेनेरियो में जी-20 देशों के शीर्ष नेता पहुंचेंगे। इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील दौरे पर 18-19 नवंबर को जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नाइजीरिया और गुयाना का दौरा भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के विदेश दौरे की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्राजील से पहले प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर को अफ्रीकी देश नाइजीरिया की यात्रा पर जाएंगे। नाइजीरिया के बाद पीएम मोदी ब्राजील पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा कई मायनों में खास है क्योंकि 17 साल के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अफ्रीकी देश के दौरे पर आ रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ब्राजील में जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर कई अन्य वैश्विक नेताओं से मुलाकात के भी कार्यक्रम हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 19-21 नवंबर तक दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की गुयाना यात्रा इस मायने में खास है क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1968 के बाद यह पहली यात्रा होगी।

भारत-कनाडा विवाद का जल्द हल निकाल लेंगे: कैमरून

नई दिल्ली। भारत-कनाडा विवाद को लेकर मंगलवार को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम संप्रभुता और कानून के प्रति काफी गंभीर हैं। हमारे मित्र और साझेदार भारत-कनाडा विवाद का जल्द हल निकाल लेंगे। जांच के बाद इस मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उच्चायुक्त ने कहा कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें बधाई दी। यूके और यूएस लंबे रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों के बीच सुरक्षा, सैन्य, खुफिया सहयोग है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप हमारे सहयोग के बड़े समर्थक हैं। हम सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करते हैं। ब्रिटेन के डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह को लेकर लिंडी कैमरून ने कहा कि मुझे ब्रिटेन का हिस्सा होने पर बहुत गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट की सीढ़ियों पर दीये जलाते हैं। हमारे पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जब ऐसा करते थे तो मुझे बहुत गर्व होता था। इस साल हमारे प्रधानमंत्री ने दिवाली पर दीये जलाए तो भी मुझे गर्व हुआ।

स्टारलिंक की भारत में एंट्री, ज्योतिरादित्य ने किया ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश एलन मस्क के स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस देने के लिए तैयार है। सेवा से जुड़ी एकमात्र शर्त यह है कि यह भारत की सख्त सुरक्षा और नियामक शर्तों का पालन करती है। सिंधिया के अनुसार, किसी भी अन्य उपग्रह सेवा की तरह, स्टारलिंक को सरकार के लाइसेंसिंग प्रारूप में हर चिंता का समाधान करके भारत के सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरा करना होगा। मानदंड पूरे होने पर लाइसेंस दे दिया जाएगा। सिंधिया ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सभी बक्सों की जांच हो जाने के बाद सरकार को स्टारलिंक का स्वागत करने में खुशी होगी। भारत में काम करने के लिए, स्टारलिंक को एक स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसमें संभावित डेटा और साइबर खतरों के खिलाफ सुनिश्चित सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। सिंधिया ने आगे उल्लेख किया कि सरकार के मानदंड सख्त हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे सभी उपग्रह प्रदाताओं पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा। वर्तमान में छह्द्धश सैटेलाइट कम्युनिकेशंस (रिलायंस) और वनवेब (भारती समूह द्वारा समर्थित) जैसी सैटेलाइट सेवा प्रदाता कंपनियां भारत में सैटेलाइट संचार लाइसेंस रखती हैं।

भारत और चीन की सेनाएं हफ्ते में एक बार गश्त करेंगी

नई दिल्ली। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के डेमचोक और देपसांग इलाकों में हर हफ्ते एक समन्वित गश्त करने पर सहमति जताई है और वहां गश्त का एक दौर पहले ही पूरा कर लिया है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में डेमचोक और देपसांग दोनों में सैनिकों की वापसी पूरी करने के बाद दोनों पक्षों ने महीने के पहले हफ्ते में समन्वित गश्त शुरू की थी। दोनों पक्षों ने देपसांग और देपसांग में हर हफ्ते एक-एक गश्त करने पर सहमति जताई है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में एक गश्त भारतीय सैनिकों की तरफ से और एक गश्त चीनी सैनिकों की तरफ से की जाएगी। दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर कई दौर की बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के लिए समझौते पर पहुंचे हैं। भारतीय और चीनी पक्ष इन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर जमीनी कमांडर स्तर की बातचीत जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने समझौतों पर पहुंचने के बाद सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए सत्यापन गश्त भी की है।

क्या संविधान में लिखा कि विधायक खरीदे जाएं : राहुल

गोंदिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान के मुद्दे को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछा कि क्या संविधान में लिखा है कि सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदना चाहिए? महाराष्ट्र के गोंदिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि पीएम मोदी ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने इसे पढ़ा होता तो वे इसका सम्मान करते। हाथ में संविधान पकड़कर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र बचा है तो इस किताब की वजह से। इस किताब को तैयार करने में डॉ. बीआर आंबेडकर, महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका रही। जबकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस 24 घंटे किताब पर हमला करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या इस संविधान में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए किसी को भी विधायकों को खरीदना चाहिए? सोमवार को भाजपा ने संविधान को लेकर दिए जा रहे भाषण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की थी। भाजपा ने कहा था कि राहुल गांधी लगातार संविधान को लेकर भाजपा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

नतीजों के बाद महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए फिर से मचेगी खींचतान

हिमांशु मिश्र

क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों महाविकास आघाड़ी (एमवीए) और सत्तारूढ़ महायुति में बड़ा खेल होगा? क्या दोनों गठबंधन में शामिल दल चुनाव बाद भी अपने पुराने गठबंधन के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे? यह सवाल इसलिए कि वर्तमान विधानसभा के पांच साल के कार्यकाल में जिस सीएम पद के सवाल पर विवाद के कारण राज्य को तीन-तीन मुख्यमंत्री मिले और दो दलों शिवसेना व एनसीपी में टूट हुई, उसी अहम सवाल पर दोनों गठबंधन चुप हैं। सीएम पद के अलावा कई अहम मुद्दों पर दोनों गठबंधनों के सहयोगियों के बीच गहरे मतभेद हैं। अहम तथ्य यह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों के लिए सभी मतभेद भुला कर सरकार गठन के लिए महज 72 घंटे होंगे।

गौरतलब है कि शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने बनाने वाली भाजपा ने चुनाव में उन्हें अपना चेहरा नहीं बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। दूसरी ओर एमवीए के अहम सहयोगी एनसीपी (शरद) के मुखिया शरद पवार ने भी शाह की तर्ज पर कहा है कि गठबंधन नतीजे आने के बाद सीएम पद के लिए विमर्श करेगा। उनकी पार्टी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि अधिक सीटें जीतने वाले दल का ही हक इस पर बनता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उद्धव ठाकरे ने इसी सवाल पर राजग से नाता तोड़ लिया, वह एमवीए की सरकार में दूसरे दल के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे?

एमवीए में जाति जनगणना और सावरकर के सवाल पर मतभेद हैं। शिवसेना नहीं चाहती कि राज्य में कांग्रेस सावरकर के खिलाफ बोले। हिंदुत्व के जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी एमवीए में अलग-अलग सुर सामने आते रहे

हैं। दूसरी ओर महायुति में शामिल एनसीपी (अजीत) ने भाजपा के मुख्य नारे बटेंगे तो कटेंगे पर ही सवाल उठा दिया है। इससे पहले भाजपा और एनसीपी में नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर ठनी।

बीते चुनाव में जनादेश के बाद सीएम पद पर मतभेद के बीच अचानक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी। हालांकि इसके 80 घंटे बाद शिवसेना ने एनसीपी-कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव सीएम बने। ढाई साल बाद शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनी। इसी बीच एनसीपी भी दो फाड़ हो गई। इस उथलपुथल में महाराष्ट्र ने पांच साल में तीन-तीन सीएम देखे।

दोनों गठबंधनों में शामिल सभी दलों के लिए सीएम पद का सवाल सबसे अहम है। शिवसेना का राजग से अलग होना, शिवसेना में टूट, एनसीपी में विद्रोह, भाजपा और उद्धव ठाकरे में अनबन सबके पीछे सीएम का ही पद था। बीते विधानसभा चुनाव के बाद राजग से शिवसेना से अलग करने के लिए भले ही एनसीपी-कांग्रेस ने उद्धव को सीएम बनाने की शर्त मान ली, मगर अब ऐसी स्थिति नहीं है। अरसे बाद मजबूत हो कर उभरी कांग्रेस की महत्वाकांक्षा भी सरकार का नेतृत्व करने की है। यही स्थिति एनसीपी (शरद) की भी है। मजबूरी में शिंदे को सीएम बनाने वाली भाजपा की शुरू से ही सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा रही है।

दोनों गठबंधनों में शामिल दलों का जोर सीटें बढ़ाने पर है, जिसके जरिये सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने के साथ मोलभाव किया जा सके। इसके लिए शिंदे गुट का पूरा जोर मराठा वोट बैंक पर कब्जा करने की है। वहीं, अजीत गुट मूल एनसीपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहता है। भाजपा ओबीसी-अगड़ा समीकरण के सहारे पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहती है।

जनादेश चाहे जिस गठबंधन के पक्ष में हो, मगर नतीजे आने के बाद सीएम पद के सवाल पर खींचतान मचना तय है। अहम तथ्य यह है कि सरकार गठन करने के लिए दोनों गठबंधनों के पास महज 72 घंटे का समय ही बचेगा। गौरतलब है कि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जबकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा।

महाराष्ट्र को महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत-मोदी

सोलापुर। महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र को महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है जिसका एकमात्र उद्देश्य राज्य का विकास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि जिस वाहन पर एमवीए के लोग यात्रा कर रहे हैं वह सबसे अस्थिर है। वे आपस में लड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति में विश्वास करने वाली महायुति की सरकार काम करती है, तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, सोलापुर के लोगों ने ये देखा है। सोलापुर के लोग जिस विकास की मांग दशकों से कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स दशकों से लटके थे, महायुति सरकार ने उन्हें पूरा करके दिखाया है।

फर्जीवाड़ा कर जमीन बिक्री के मामले में तत्कालीन तहसीलदार राजस्व निरीक्षक, पटवारी सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज

मनेन्द्रगढ़। फर्जीवाड़ा कर जमीन बिक्री करने के मामले में तत्कालीन तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी सहित पांच आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनेंद्रगढ़ के न्यायालय की ओर से सिटी कोतवाली को आदेश दिया गया है, जिसमें उल्लेख है कि वार्ड क्रमांक 13 जंहगीर मोहल्ला मनेन्द्रगढ़ एमसीबी निवासी आवेदक अरविंद कुमार वैश्य द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादीगण मनेन्द्रगढ़ के स्थायी निवासी हैं।

नदीपारा मनेन्द्रगढ़ पटवारी हलका नंबर 14 में राजस्व भूमि खसरा नंबर 198/1 रकबा 22 एकड़ स्थित है, जो शासकीय जमीन थी एवं शासकीय भूमि का पट्टा परिवादीगण के दादा मूलचंद लंहगीर को मिली थी। दादा की मृत्यु के बाद स्व. वृंदावन वैश्य एवं सेवाराम के नाम राजस्व अभिलेख में विरासतन हक से दर्ज किया गया, लेकिन राजेश पुरी पिता सत्यदेव पुरी ने परिवादी के पिता एवं उनके भाईयों ज्ञानचंद वैश्य, वृंदावन वैश्य एवं सेवाराम वैश्य से विधि विरूद्ध तरीके से भूमि को 1978 में क्रय कर लिया था, जबकि जमीन शासकीय पट्टे पर मिली थी, जिससे जमीन की बिक्री के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी थी, लेकिन बिना कलेक्टर की अनुमति बिक्री कराई गई थी।

मामले में गलत भूमि बिक्री के संबंध में शिकायत अपर कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ को सौंपी गई। अपर कलेक्टर ने 29 अप्रैल 2021 को आदेश पारित कर राजेश पुरी के पक्ष में 1978 में बिक्री का पंजीयन निरस्त कर दिया साथ ही भूमि शासन के पक्ष में करने का आदेश पारित किया गया, जिससे भूमि शासन के नाम से राजस्व अभिलेखों में सुधार कर दर्ज कर दी गई। राजेश पुरी एवं परिवादी ने अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील की, जिसे अपर कमिश्नर अंबिकापुर ने निरस्त कर दिया। इसके बाद राजस्व मंडल, उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई जिसे उच्च न्यायालय ने कमिश्नर न्यायालय में लंबित अपील को स्थपित कर दिया। मामले में अपील लंबित रहने के दौरान भूमि की बिक्री के लिए राजेश पुरी, पटवारी सुरेन्द्र पाल सिंह एवं राजस्व निरीक्षक संदीप सिंह ने फर्जी दस्तावेज एवं झूठा प्रतिवेदन तैयार कराया।

तत्कालीन पटवारी अनुराग गुप्ता तथा तत्कालीन तहसीलदार बजरंग साहू ने मिलकर राजस्व अभिलेख 8 अक्टूबर 21 को शान के नाम पर दुरूस्त किया था, फिर बिना किसी आदेश राजस्व अभिलेखों में 7 दिसंबर 21 को खसरा 198/1 में शासन का नाम हटाकर राजेश पुरी का नाम फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों ने मिलीभगत कर कई लोगों को जमीन की बिक्री कर दी है। मामले में आरोपियों वर्तमान में कोरबा जिले में कार्यरत तत्कालीन तहसीलदार बजरंग साहू, लुधियाना (पंजाब) निवासी राजेश पुरी, मनेंद्रगढ़ झगराखंड रोड निवासी पटवारी सुरेंद्र पाल सिंह, राजस्व निरीक्षक मनेंद्रगढ़ संदीप सिंह एवं हर्रापारा बैकुंठपुर निवासी पटवारी अनुराग गुप्ता के विरूद्ध धारा धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया गया है।

नक्सलियों ने एक बार फिर मुखबिरी के आरोप में एक युवक की हत्या कर दी

बीजापुर। जांगला थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम पोटेनार के जंगल में नक्सलियों ने एक बार फिर कथित जनअदालत लगाकर मुखबिरी के आरोप में एक ग्रामीण युवक माड़वी दुलारु निवासी ग्राम माटवाड़ा की निर्मम हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने ग्राम पोटेनार के जंगल में सोमवार को जनअदालत लगाई थी। इस तालीबानी जनअदालत में माड़वी दुलारु पर मुखबिरी का आरोप लगाया गया था। जिसे बिना किसी सुनवाई या बचाव का मौका दिए, नक्सलियों ने उसे सजा-ए-मौत का फरमान सुना दिया और उसकी हत्या कर दी। बीजापुर एएसपी चंद्रकांत गवर्णा ने बताया कि इस मामले की जानकारी आज मंगलवार सुबह पुलिस को मिलते ही जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही नक्सली हत्या की बात स्पष्ट होंगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने माटवाड़ा निवासी माड़वी दुलारू का अपहरण कर लिया था। जिसके बाद एक दिन पहले पोटेनार गांव में जनअदालत लगाकर इस पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया गया। नक्सलियों ने गांव वालों के सामने कहा कि यह पुलिस के साथ मिलकर हमारी सूचना देता है। इसलिए इसे मौत की सजा दी जा रही है, जिसके बाद धारदार हथियार से वारकर उसे मार डाला।

उल्लेखनिय है कि नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में वर्ष 2001 से 2023 तक नक्सलियों ने लगभग 1,774 आदिवासियों की हत्या कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिर्फ बीजापुर जिले में ही 783 आदिवासियों की नक्सलियों ने हत्या की हैं, यह सिलसिला आज भी बीजापुर जिले में जारी है, जहां नक्सली आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। सलवा जुडूम के दौर में नक्सलियों ने बस्तर में सबसे ज्यादा खूनी खेल खेला है। हालांकि, पिछले 23 सालों में पहली बार अब पुलिस नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। यह भी विदित हो कि वर्ष 2005 से 2006 में जब बस्तर में नक्सलवाद अपने चरम पर था। तब सलवा जुडूम की शुरुआत की गई थी। इसी दौर में आम नागरिकों पर सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा हुई थी। वर्ष 2006 में सिर्फ बीजापुर में ही 297 आदिवासियों की नक्सलियों ने हत्या की थी कईयों को घर से बेघर कर दिया गया था, तब नक्सलियों द्वारा बस्तर में जमकर खूनी खेल खेला गया था।

अब भालुओं का आतंक, कोरबा में मवेशी चरा रहे ग्रामीण पर हमला

10 मिनट तक लिया लोहा, घायल होकर अस्पताल पहुंचा

कोरबा। कोरबा जिले के मोरगा चौकी अंतर्गत मोरगा के ग्राम जुनापारा निवासी अमीर सिंह (55) अपने स्वयं के मवेशियों को चराने ग्राम के पास जंगल में गया था। जानकारी के अनुसार, मवेशी चराने जंगल पहुंचे ग्रामीणों पर एक मादा भालू ने अपने दो बच्चों सहित हमला कर उसे घायल कर दिया।

बताया जा रहा है कि एकाएक झाड़ियों से निकले मादा भालू और उसके दो बच्चों ने उस पर हमला कर दिया। हाथ-पैर और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान है। इसके बाद भी किसी तरह ग्रामीण ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और ग्राम पहुंचा।

जिसके बाद 112 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी-उपरोड़ा पहुंचाकर भर्ती कराया गया हैं। वन विभाग ने घायल व्यक्ति को सहायता राशि भी प्रदान की है। घायल अमीर सिंह की मानें तो अकेले अपने स्वयं के ही गाय, भैंसों को चराने जंगल की ओर गया था। जहां उसका सामना एक मादा भालू से पहले हुआ।

फिर दो छोटे शावकों ने हमला कर दिया। उनसे भी संघर्ष हुआ भालुओं के शिकार से उसके हाथ और शरीर पर काफी गहरी छोटी आई। जब वो किसी तरह चीखपुकार मचाई तो तब भालू भाग खड़े हुए। किसी तरह जान बचाकर वह गांव के नजदीक पहुंचकर एक किसान को पूरी घटना की जानकारी से अवगत कराया।

इसके बाद परिजनों द्वारा डायल-112 व वन विभाग को सुचित किया जो मौके पर मौजूद रहे। सूचना मिलते ही टीम द्वारा घटनास्थल पहुंचकर बेहतर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी उपरोड़ा लाकर भर्ती कराया गया। घटना की सूचना टीम द्वारा की संबंधित चौकी प्रभारी महोदय मोरगा को दिया गया। वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया गया है और घटना स्थल के लिए टीम रवाना हो गई है।

पकड़ा गया अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का झूठ

दिलबंधु के जिंदा होने की ग्राम सचिव द्वारा पुष्टि के बाद आयोग के चेयरमैन के षड़यंत्र का पर्दाफाश

उदयपुर। पिछले चार दिनों से अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह द्वारा सचिव की पुष्टि के बिना ही बनाए गए निराधार रिपोर्ट द्वारा सनसनी मचाने के प्रयास पर पानी तब फिर गया जब घाटबर्रा के दिलबंधु मझवार को मृत नहीं परंतु जीवित पाया गया। भानुप्रताप सिंह जो की काँग्रेस के एक कार्यकर्ता भी है उन्होंने दावा किया था की परसा खदान की ग्रामसभा के प्रस्ताव मे एक मृतक दिलबंधु के भी हस्ताक्षर है। इसकी तहकीकात में राज्य प्रशासन और जागृत समाचार माध्यमों द्वारा दिलबंधु के जिंदा होने की पुष्टि की गई। सोमवार के दिन कथित मृतक की पहचान को प्रमाणित करने के लिए उदयपुर तहसील कार्यालय पर ले जाया गया जहां यह पाया गया की रजिस्टर में ग्रामसभा के प्रस्ताव में जिस दिलबंधु के हस्ताक्षर हैं वह बाकायदा वही है और जीवित है।

यह उल्लेखनीय है की रायपुर स्थित कुछ तत्व द्वारा सरगुजा जिले की परसा कोयला खदान के लिए आयोजित की गई ग्राम सभा को फर्जी बताकर अनजान माध्यमों द्वारा गलत समाचार प्रकाशित कर उसे सोशल मीडिया में चमकाकर छत्तीसगढ़ के खदान क्षेत्र को बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है की इसी आयोग ने हाल ही में फर्जी ग्रामसभा के आक्षेपों को घनिष्ठ जांच पड़ताल के बाद खारिज कर दिए थे। यहाँ तक की अभी तक परसा खदान के विकास विरोधी तत्व अपने दावों को किसी भी न्यायालय में साबित कर नहीं पाए है। हालांकि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह बिना किसी आधार पर सिर्फ चालीस लोगों से आवेदन लेकर एक तरफ रिपोर्ट जारी कर दी थी जिसे आयोग के सचिव ने मान्य किया नहीं था। याद दिला दें की परसा खदान के आसपास कुछ दस हजार स्थानीय रहते हैं। रायपुर के एक कथित अभियानकारी जो की चार पन्ने की रिपोर्ट में सचिव के दस्तखत ना होने की हकीकत को छुपाने के लिए आगे के सिर्फ तीन ही पन्ने अपने सोशल मीडिया पर डाल कर गलत दावे भी कर दिए थे जो अब झूठे साबित हो गए है ।

अगनुराम मझवार के 28 वर्षीय पुत्र दिलबंधु मझवार ने समाचार माध्यमों को बताया की, मैँ ग्राम घाटबर्रा के अगरियापारा का निवासी हूँ। मेरा आधार कार्ड क्रमांक 9605 27**** है। मुझे आप के माध्यम से पता लगा की कुछ लोगों द्वारा मेरे मृत होने की खबर फैलाई जा रही है। जिसका मैं खंडन करता हूँ। इसके लिए मैं मेरे गांव के ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल राम यादव से भी संपर्क किया हूँ। जिसके लिए वे मेरा पंचनामा सभी साक्ष्यों के हस्ताक्षर लेकर मुझे दिया है। इसकी छायाप्रति मैं आज जिलाधीश महोदय और एसडीएम साहब को जमा कराया हूँ। मैंने ही जनपद पंचायत द्वारा परसा कोयला ब्लॉक के लिए दस सितंबर को आयोजित ग्राम सभा के उपस्थिति पंजी में अपना हस्ताक्षर किया है। कुछ लोगों की सोची समझी षड्यन्त्र के तहत मेरे मृत होने की झूठी खबर फैलाने के चलते मेरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है। जिससे मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिलबंधु ने जागृत समाचार माध्यमों को धन्यवाद देते हुए कहा की मेरा सच अब सभी के सामने आ जाएगा।

वहीं इस सिलसिले में ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल राम यादव ने कहा कि जिस दिन गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई थी उस दिन मेरे समक्ष ही उपस्थित ग्रामवासियों ने हस्ताक्षर किया है। इसमें से दिलबंधु को कुछ मीडिया के माध्यम से मृत होने की बात का पता चला है जो की सरासर गलत है। इस झूठी खबर का मैं खंडन करता हूँ। आज मैंने दिलबंधु का जीवित होने के लिए पंचनामा तैयार किया है जिसे माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस दौरान सारी वैधानिक मंजूरियों के साथ राजस्थान सरकार का विद्युत उत्पादन निगम अपनी परसा खदान को कार्यान्वित करने के लिए तैयारी कर रहा है जिसके चलते आदिवासी जिले में 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। सरकारी और समाचार माध्यमों की निजी स्वार्थ के लिए चलाए जा रहे महंगे अभियान का भंडाफोड़ होने के बाद अब देखना होगा की दिलबंधु की अस्तित्व की लड़ाई क्या मोड़ लेती है और वह झूठी खबर फैलाने वालों पर क्या कार्यवाही करेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नगर पालिका कर्मचारियों का तीन दिवसीय हड़ताल शुरू

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा नगरीय निकायों में चरणबद्व तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसके तहत मांग को नगर पालिका कवर्धा के नियमित कर्मचारी आज 12 से 14 नवंबर तक यानी तीन दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। ये बिलासपुर स्थित नेहरू चौक विकास भवन में हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल अवधि में निकाय के कार्य बंद रखेंगे। इसके बाद भी शासन द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती है, तो सभी अधिकारी-कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ के जिलाध्यक्ष बद्रीराम साहू ने बताया कि हड़ताल में जाने की सूचना नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दे दी गई है। हमारी प्रमुख मांग नगरीय निकाय में प्रत्येक माह एक तारीख को वेतन भुगतान ट्रेजरी (कोषालय) के माध्यम से हो। निकायों में ठेका प्रथा बंद हो व 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाए। नगरीय निकाय में अन्य विभाग की भांति ओल्ड पेंशन लागू हो।

स्कूल में घुसकर बच्चों की पिटाई, प्राचार्य ने की शिकायत

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र के हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम टेमरी में कुछ युवकों ने घुसकर बच्चों के साथ मारपीट की है। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य की शिकायत बाद नांदघाट थाना में आरोपी लिखेन्द्र निषाद व उसके अन्य 7-8 साथी के खिलाफ धारा 115(2), 132, 191(2), 191(3), 221, 296, 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाने में स्कूल के प्राचार्य सनक प्रकाश महिलांगे ने अपने रिपोर्ट में बताया कि स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। तभी दोपहर 12 बजे स्कूल मे शोर गुल की आवाज सुनाई देने पर मौके पर गए। बाहर के लड़के करीबन 7-8 लोग स्कूल अंदर घुसकर स्कूली बच्चों के साथ गाली-गलौच कर रहे थे। साथ ही रॉड, क्रिकेट स्टंप से मारपीट कर रहे थे। जान से मारने की धमकी दे रहे थे। शिक्षकों के आने में बाद ये लड़के भाग गए। बच्चों ने बताया कि इसी माह 8 नवंबर को ये आरोपी स्कूल ग्राउंड में भी गाली-गलौच किए थे। मारपीट करने से छात्र जावेद, देवेन्द्र, सुरज, आदित्य, यशवंत, आदित्य दास मानिकपुरी, बलवंत को चोट आई है।

अवैध धान परिवहन पर करें कार्रवाई : कलेक्टर

बेमेतरा। प्रदेश के कृषि प्रधान बेमेतरा जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। धान बेचने के लिए पूरे जिले से करीब एक लाख किसान ने पंजीयन कराया है। यह खरीदी 15 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस खरीदी को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि धान बेचने आए किसान को केंद्र में कोई दिक्कत न हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। साफ-सफाई पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। किसी भी स्थिति में खरीदी में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए सतर्क रहे। अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्रवाई करें। धान खरीदी कार्य में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी एसडीएम से कहा कि वह अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत एक व्हाट्सएप ग्रूप बनाकर धान खरीदी केंद्र में पैनी नजर रखें। सतत मॉनिटरिंग करें। प्रत्येक सप्ताह शनिवार को खरीदी की व्यवस्था, खरीदे गए धान की मॉनिटरिंग करें। धान खरीदी छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता में है। धान खरीदी के लिए यदि कहीं कोई कमी या अव्यवस्था हो, तो इसे तत्काल दुरूस्त करें।

360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के वेद प्रकाश अध्यक्ष

जगदलपुर। बस्तर संभाग में 624 वर्षों के समृद्ध विरासत की परंपरा के निर्वहन की ऐतिहासिक पहचान के साथ स्थापित 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के वर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने के पर श्रीजगन्नाथ मंदिर में आज आहूत बैठक में समाज के संचालक पदेन पानीग्राही राधाकांत पानीग्राही एवं पदेन पाढी उमाशंकर पाढ़ी एवं पूर्व अध्यक्ष दिनेश पानीग्राही एवं हेमंत पांडे के मार्गदर्शन एवं वर्तमान 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वर खंबारी की अध्यक्षता में समस्त क्षेत्रीय समितियां के पदाधिकारी एवं समाज के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में क्षेत्रिय समितियों से प्राप्त सूचि के आधार पर नवीन प्रबंध कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति किया गया। जिसमें 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के वेद प्रकाश पांडे निवासी ग्राम गुमडेल को अध्यक्ष पद हेतु चयन किया गया। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए जिवेंद्र कुमार पांडे, ग्राम गुनपुर सचिव पद के लिए देवशंकर पंडा का चयन किया गया।

झगड़ा नहीं करने की बात कहने पर घर में घुसकर मारपीट

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सिवनी में लड़ाई झगड़ा नहीं करने की बात कहने को लेकर घर के अंदर घुसकर मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को नैला चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार दीपावली की रात्रि करीबन 8.30 बजे प्रफुल्ल धीवर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहे थे जिसपर शिव कुमार बरेठ ने लड़ाई झगडे मत करो कहने पर घरेलू झगड़े में तुम मना करने वाले कोन हो बोलने वाले कहते हुए गाली गलौज दी। जिसके बाद शिव कुमार बरेठ वहां से अपने घर चला गया। जिसके कुछ देर बाद फ्रफुल्ल,पंकज, पृथ्वी धीवर आए और घर के अंदर घुसकर मारपीट की पंकज धीवर ने अपने हाथ में रखे चाकू से पेट और सीने को मारा जिससे खून निकलने लगा था। नैला चौकी उप थाना में अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। आरोपियों को उनके गांव सिवनी में होने पर घेरा बंदी कर पकड़ा गया जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मारपीट और चाकू से हमला करने का जुर्म स्वीकार किया है।

असली नाम-पता छिपाकर बस्तर में रह रहे 20 संदिग्ध मुस्लिम सहित 43 जेल दाखिल

कोंड़ागांव। जिले के पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध लोगो पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक कौशेलेन्द्र देव पटेल के निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव रूपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित कर केशकाल थाना क्षेन्तार्गत 4 संदिग्ध एवं कोंड़ागांव थाना क्षेत्रान्तर्गत 16 संदिग्ध बपना असली नाम-पता छिपाकर बस्तर के अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे उत्तर प्रदेश, बिहार के कुल 20 लोगो के संदिग्ध पाये जाने पर इस्तागासा तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, इसमें लगभग सभी उत्तर प्रदेश, बिहार के मुस्लिम पाये गये हैं। जिनका जेल वारण्ट बनने से आज मंगलवार को केन्द्रीय जेल जगदलपुर दाखिल किया गया। विदित हो कि सोमवार को भी कोंड़ागांव पुलिस पश्चिम बंगाल, बिहार के संदिग्ध 23 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस तरह विगत दो दिनों में गिरफ्तार कुल 43 संदिग्धों में जिन्हे जेल भेजा गया है, इसमें कितने बंगलादेशी या रोहिंग्या है, यह जांच का विषय है। बस्तर के आदिवासी बाहूल्य पांचवी

अनुसूचित क्षेत्र की डेमोग्राफी को बचाने के लिए इस तरह की सघन जांच संपूर्ण बस्तर संभाग में किये जाने की आवश्यकता है। इस विषय पर बस्तर संभाग के हिंदू संगठन पुलिस को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग कर चुका है, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसाार कोण्डागांव जिले से अब तक कुल 43 संदिग्धों को जो अपनी उपस्थिति छिपा रहे थे, उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया और जो अपना असली नाम व पता छिपा रहे थे, कडाई से पूछताछ करने पर सभी ने अपना अपना नाम व पता बताए, जिनका आचरण संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुये संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार बनाये रखने धारा 128 बीएनएसएस (109 जाफौ.) का इस्तागासा तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिनका वारण्ट बनने से केन्द्रीय जेल जगदलपुर में दाखिल किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार 20 संदिग्धों में जिन्हे जेल भेजा गया है उनमें साहिल पुत्र अबरार, बेरूवा उत्तर प्रदेश, हसीब पिता मेहबूब, बाकीपुर जटनी उत्तर प्रदेश, मो. वसीम पिता शमीम हुसैन,महलोली उत्तर प्रदेश, बारिस पिता गफ्फार सिंह, जलालपुर उत्तर प्रदेश, इंतजार हुसैन पिता रहिश दूल्हा, सोंडा उत्तर प्रदेश, मतीन पिता यासीन, बाकीपुर जटनी उत्तर प्रदेश, मो0 फखरूद्दीन पिता मो0 सरदीक, ईसलामपुर बिहार, मो0 उमर पिता मो यूनस, केवटगामा बिहार, मो0 फिरोज पिता मो0 जाहिर, केवटगामा बिहार, मो0 यूनूस पिता मो0 तसलीम, पछियारीरही केवटगामा, फरमान पिता नशरूद्दीन, महेलवाला उत्तर प्रदेश, वासिल पिता युसुफ, महेलवाला उत्तर प्रदेश, रिहान मलिक पिता मोहम्मद यामीन, उत्तर प्रदेश, वसिम पिता नूर मोहम्मद, महेलवाला उत्तर प्रदेश, रिजवान मलिक पिता यामिन, लखीपुरा उत्तर प्रदेश आदि को गिरफ्तार किया गया है।

हाथियों का दल पहुंचा कांकेर बॉर्डर

■ ड्रोन से की जा रही है निगरानी, वन विभाग ने बंद कराई बिजली सप्लाई

कांकेर। कांकेर में एक बार फिर हाथियों का दल लौटकर दुधावा के करीब साईमुंडा के जंगल तक पहुंच गया है। ये सिकासेर दल के हाथी हैं, जिसके 15 सदस्यों ने बीती रात जिले में प्रवेश किया, लेकिन सुबह तक वापस धमतरी जिले में चले गए। सोमवार को ये अपने दल के अन्य हाथियों के साथ कांकेर जिला के बार्डर पर ही मौजूद रहे। वन विभाग ने इनकी सुरक्षा के लिए इलाके की बिजली सप्लाई बंद करा दी है। सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व अभ्यारण में चार दिनों से घूम रहे सिकासेर दल के हाथी शनिवार रात ही कांकेर जिले में दुधावा के करीब साईमुंडा पहुंचे लेकिन वे यहां से आगे नहीं बढ़े। सूचना मिलते ही विभाग का अमला रात में हाथियों व लोगों की सुरक्षा के लिए इलाके में तैनात हो गया।

सोमवार को दिनभर जंगल में आराम करने के बाद रात में 15 हाथी कांकेर जिले के साईमुंडा इलाके में पहुंच गए। हाथी बस्ती के करीब थे, लेकिन बस्ती

में नहीं आए। वे जंगल में ही भोजन के लिए पेड़-पौधों को तोड़ फल फूल खाते रहे। सुबह होने तक ये वापस कांकेर जिले के बार्डर से बाहर धमतरी जिले में पहुंच गए, जो कांकेर जिले के बार्डर से महज 3-5 किमी दूर है।

डिप्टी रेंजर हरीश कोड़ोपी ने बताया हाथियों की सुरक्षा के लिए इलाके में खेत व बस्ती के बाहर के इलाके में बिजली सप्लाई बंद करा दी गई है। हाथी पिछले कुछ वर्षों से सितंबर-अक्टूबर में साईमुंडा तक आ रहे हैं। आगे पहड़ी इलाका होने के कारण वे यहां से वापस लौट जाते हैं। भोजन की तलाश में इस इलाके में लंबे समय तक घूमते रहते हैं। जिसे देखते वन विभाग का अमला पूरे समय यहां तैनात है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री साय ने गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गजानन माधव मुक्तिबोध की 13 नवम्बर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हिन्दी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर और इस युग के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कर्मभूमि छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव रही है।कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार के रूप में उन्होंने अमूल्य साहित्य की रचना की है। उन्हें आधुनिक हिंदी कविता के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री गजानन माधव मुक्तिबोध को स्मरण करते हुए कहा है कि मुक्तिबोध जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी से अमिट छाप छोड़ी है।

प्रदीप टंडन पीएचडीसीसीआई की राज्य परिषद के चेयरमैन नियुक्त

रायपुर। प्रदीप टंडन पीएचडीसीसीआई की राज्य परिषद के चेयरमैन नियुक्त हुए है। पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पिछले 119 वर्षों से भारतीय उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्य स्त्रोत के रूप में काम कर रहा है। चैम्बर दूरदर्शी, सक्रिय ,गतिशील एवं अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है,जो उद्योग की प्रगति के लिए सरकार के साथ भागीदार के रूप मे कार्य करता है। पीएचडीसीसीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, सदभाव और एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ जमीनी स्तर पर काम करता हैं, ये संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई क्षेत्रों में 1,50,000 से अधिक छोटे बड़े एवम मध्यम उद्योगों से जुड़ा हुआ है। पीएचडीसीसीआई भारत और विदेशों में दूतावास और हाय कमीशन के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यावसायिक अवसरों को लाने के लिए भी काम कर रहा हैं। पीएचडीसीसीआई का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बहरीन में 6 जीसीसी देशों के लिए स्थापित है। पीएचडीसीसीआई ने पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योग संघों और संगठनों को सहयोजित किया हैं।

स्क्वैश के राष्ट्रीय खिलाड़ी सूर्यांश मिश्रा सम्मानित

रायपुर। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा विगत दिनों आर्शिवाद भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में स्क्वैश के राष्ट्रीय खिलाड़ी सूर्यांश मिश्रा को राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2023 -24 जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी छत्तीसगढ़ की अंडर -14 टीम में चयन होने पर सम्मानित किया गया। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा सिल्वर मैडल और उपहार देकर यह सम्मान उन्हे प्रदान किया गया। प्रतिभावान खिलाड़ी सूर्यांश अनुराग मोमेंटो हाउस के संचालक अनुराग मिश्रा के पुत्र हैं।

हादसे का शिकार होते-होते बची दुर्ग आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस

रायपुर। विशाखापट्नम से दुर्ग आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ओडिशा के नुआपाड़ा रोड में हादसे का शिकार होते-होते बची। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस कल रात करीब 10 बजे विशाखापट्टनम से दुर्ग जा रही थी। इस बीच ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता से रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा पत्थर देखा और ट्रेन को रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट से लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दिया। ट्रेन रोकने के बाद लोको पायलट ने इस बारे में स्टेशन मास्टर को सूचित किया। जल्द ही रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक से पत्थर को हटा दिया, जिसके बाद करीब एक घंटे बाद ट्रेन की आवाजाही सामान्य हो सकी। नुआपाड़ा पुलिस स्टेशन से एक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी कि ट्रैक पर पत्थर किसने और क्यों रखा था। वहीं, लोगों ने लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ की सराहना की, जिसकी वजह से एक संभावित दुखद दुर्घटना टल गई।

बाल्को के ब्लीचिंग प्लांट में अवैध रेत भंडारण का मामला उजागर

कोरबा। अवैध रेत भंडारण पर कड़ाई बरतने के निर्देश विभाग को मिला हुआ है। इस मामले को लेकर बाल्को एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार बाल्को के ब्लीचिंग प्लांट में अवैध रेत भंडारण का मामला सामने आया है। माइनिंग विभाग की टीम ने असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर उत्तम खूंटे के नेतृत्व में छापा मारकर 12 गाडिय़ां जप्त कीं, जिनमें अवैध रूप से रेत भरी हुई थी। बता दें कि, जिले में रेत के चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करना शुरु कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच हुआ है। सूत्रों के अनुसार, रेत का अवैध भंडारण बाल्को के ब्लीचिंग प्लांट में किया जा रहा था। एसीसी इंडिया, केसीसी और एलएडंटी को भी नोटिस जारी किया गया है। छापे के दौरान माफियाओं ने अपने ड्राइवर को मौके से भगाने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने सतर्कता बरतते हुए वाहनों को जप्त कर लिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद रेत के अवैध कारोबार में शामिल लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है। जिन उद्योग घरानों को नोटिस मिली है या जब्ती की कार्रवाई हुई है उन्होने अपना पक्ष अभी नहीं दिया है।

14 से धान खरीदी, आयुक्त सहकारिता ने अधिकारियों की ली वर्चुअल बैठक

रायपुर। चाक-चौबंद व्यवस्था के निर्देश के परिपालन में सभी जिलों में कलेक्टरों के मार्गदर्शन में सहकारिता, मार्कफेड और खाद्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां तेजी पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा के लिए बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबूतरा, पीने का पानी, किसानों के बैठने की छायादार व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को धान खरीदी केन्द्रों की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने को भी कहा है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सहकारिता आयुक्त कुलदीप शर्मा ने सहकारिता विभाग के राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों की संयुक्त वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने जिला पंजीयक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को धान खरीदी की अग्रिम तैयारियों के संबंध में कडे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी तथा बैंक धान खरीदी के संबंध में अपनी जिम्मेदारी को समयानुसार पूरा करें।

धान उपार्जन केन्द्रों से बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबूतरा, पीने का पानी, किसानों के बैठने की छायादार स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। धान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त डनेज और तारपोलिन आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। धान बेचने के लिए केन्द्र में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

सहकारिता आयुक्त शर्मा ने सभी समितियों में सीसीटीव्ही कैमरे लगाने के लिए उचित जगह का चयन करने को कहा ताकि संपूर्ण परिसर कवर हो सके। उन्होंने ट्रायल रन के साथ-साथ सभी अग्रिम तैयारी 12 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को धान खरीदी नीति अनुसार स्टेक लगाने, सभी समितियों को उचित संख्या में ही टोकन जारी करने के निर्देश दिए। मौसम खराब होने अथवा बारिश होने की स्थिति में किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इसको ध्यान में रखते हुए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की जाए।

सहकारिता आयुक्त ने बैंक अधिकारियों को बैंकों में उपलब्ध माइक्रो एटीएम समितियों को उपलब्ध कराने को कहा ताकि किसानों को इससे राशि आहरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को सभी समितियों में भ्रमण कर वहां की व्यवस्था का मुआयना करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन किया जाएगा। इस अवधि में व्यवस्था से जुड़े अधिकारी न तो अनावश्यक रूप से अवकाश पर जाएंगे न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे।

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का आंदोलन खत्म

- 9 दिनों से आंदोलन पर थे सोसायटियों के कर्मचारी

धमतरी। हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। बीते 9 दिनों से संघ के सदस्य हड़ताल और धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में कर रहे थे। विष्णु देव साय सरकार ने उनकी तीन सूत्री मांगों को मान लिया है। सरकार जैसे ही मांगों को माना नाराज कर्चमारियों ने भी अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। 4 नवंबर से ही छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ के सदस्य आंदोलन पर थे। देवउठनी एकादशी के दिन अपनी मांगों के पूरा होने से कर्मचारी संघ काफी खुश है। कर्मचारी संघ से जुड़े नेताओं ने साय सरकार को धन्यवाद दिया है।

सोसायटी के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से सबसे ज्यादा राहत की सांस किसानों ने ली है। दरअसल 14 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। धान खरीदी की जिम्मेदारी सासायटियों के जिम्मे है। अगर आंदोलन खत्म नहीं होता तो धान खरीदी प्रभावित होती। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए इस बार किसानों को टोकन के लिए लाइन में लगने की जरुरत नहीं पड़ेगी। आज से टोकन कटने का काम भी शुरु हो चुका है।

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संघ के अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने कहा कि हमारी तीन सूत्री मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु भी निद्रा से जाग जाते हैं। आज के दिन प्रदेश के मुखिया ने हमारी मांगों को मान लिया है। संघ की तरह से हम शासन को धन्यवाद देते हैं। हमने अपने आंदोलन को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संघ के अध्यक्ष नरेंद्र साहू की मुलाकात सीएम विष्णु देव साय से होनी है।

क्या थी तीन सूत्री मांगें

मध्य प्रदेश सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी तीन लाख रुपए प्रति वर्ष प्रबंधकीय अनुदान राशि दी जाए। सेवा नियम 2018 के आंशिक संशोधन कर रिवाइज्ड वेतनमान लागू किया जाए। धान खरीदी गत वर्ष 2023 और 2024 में धान परिवहन के बाद धान में सुखत दिया जाए। समस्त कमीशनों को चार गुना तक बढ़ाया जाए।

शाहरुख खान को धमकी देने वाला आरोपी फैजान गिरफ्तार

रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी फैजान खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी अजय सिंह ने उसकी गिरफ्तारी की है। इस संबंध में रायपुर पुलिस को जानकारी दे दी गई है।

मामले में मुंबई पुलिस मंगलवार को रायपुर पहुंची। फैजान को अरेस्ट करने की ट्रांजिट रिमांड के साथ मंगलवार सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले आरोपी ने कहा कि वो बांदा पुलिस थाने में अपना बयान दर्ज कराने मुंबई जाएगा। वहीं आरोपी को लगातार धमकी मिल रही थी। इसकी वजह से उसने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर लिखा कि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं ऑनलाइन माध्यम से पेश होना चाहता है। इसके पूर्व आरोपी ने कहा था कि उसका फोन पांच दिन पहले दो नवंबर को चोरी हो गया था। इस संबंध में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 308 4, 351 3 4, के तहत शिकायत दर्ज है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पता है कि जिस मोबाइल नंबर से फोन किया गया था, वो नंबर छत्तीसगढ़ के रायपुर के फैजान नाम के शख्स का है। पुलिस की साइबर सेल की ओर से नंबर ट्रेस करने पर रायपुर का लोकेशन मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस फैजान को रिमांड पर लेकर मुंबई जाएगी और उससे पूछताछ करेगी।

कलेक्टर-एसएसपी ने मतदान दलों को चुनाव सामग्री के साथ किया रवाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए हो रहे उप चुनाव में 13 नवंबर को मतदान डाला जाएगा। इसके लिए मंगलवार को सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान सामग्री के साथ मतदान दलों को रवाना किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ। गौरव सिंह और एसएसपी डॉ. संतोष सिंह मौजूद रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ। गौरव सिंह ने बताया कि मतदान दलों में मतदाता और कर्मचारियों के लिए तैयारियां पूरी है। कलेक्टर ने बताया कि मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। मतदाताओं को बड़ी संख्या में मतदान केंद्र आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अभियान चलाया गया है। बता दें कि 13 नवंबर को होने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में 2 लाख 71 हजार 169 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 1 लाख 33 हजार 800 पुरुष और 1 लाख 37 हजार 317 महिला

मतदाता हैं। वहीं 52 तृतीय लिंग मतदाता हैं। इन सभी के लिए क्षेत्र को 42 सेक्टरों में विभाजित कर 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान के लिए 1064 मतदान कर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए 1532 पुलिस कर्मचारी- 5 कंपनियां कमान संभालेंगी।

मतदाता अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान के लिए 13 को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा। रायपुर के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देशित करते हुए जिले के सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने परिपत्र के माध्यम से रायपुर जिले के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। मतदान के दिन मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मतदान तिथि 13 नवंबर को निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान के लिए सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। रायपुर शहर में अधिकांश कार्यालय रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन क्षेत्र के बाहर अन्य स्थानों पर स्थित हैं। जहां क्षेत्र के मतदाता भी कार्य करते हैं।

पंजीयक आयुक्त शर्मा ने की विभागीय काम काज की समीक्षा

धान खरीदी के पूर्व व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

रायपुर। सहकारिता एवं पंजीयक तथा सहकारी संस्थाएं के आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम काज की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला व संभाग के पंजीयक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकरियो तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को धान खरीदी की पूर्व तैयारी के कड़े निर्देश दिए। बैठक में सभी अधिकारी तथा बैंक को दी गयी जिम्मेदारी को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

आयुक्त श्री शर्मा ने कहा कि बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबुतरा, पीने का पानी, किसानों के बैठने की छायादार व्यवस्था, धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त डनेज एवं तारपोलिन आदि की व्यवस्था सुश्चित रहे, किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसका विशेष ध्यान रखा जावे। सभी समितियों में सीसीटीव्ही

कैमरे लगाने के लिए उचित जगह का चयन किया जावे ताकि संपूर्ण परिसर कव्हर हो सके। ट्रायल रन के साथ-साथ सभी अग्रिम तैयारी पूर्ण करा लिया जाय। धान खरीदी नीति अनुसार स्टेक लगाए जावें। सभी समितियों हेतु उचित संख्या में ही टोकन जारी किए जावें ताकि अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। विगत वर्षों के अनुभव को देखते हुए बारिश आदि जैसी विपरीत प्राकृतिक स्थिति निर्मित होने पर अव्यवस्था उत्पन्न न हो इसकी अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करें। विगत अनुभवों को संज्ञान में लेते हुए राशि की उचित व्यवस्था हेतु सभी बैंकों में उपलब्ध माइक्रो एटीएम समितियों को उपलब्ध कराते हुए किसानों को इससे राशि आहरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

धान खरीदी के पूर्व सभी अधिकारी समितियों में भ्रमण कर व्यवस्था को देखें तथा किसी भी प्रकार की कमी संज्ञान में आने पर उचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। कोई भी अधिकारी धान खरीदी के मध्य अनावश्यक अवकाश पर नहीं रहेंगे साथ ही मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।

जनजातीय गौरव दिवस : रायपुर में 14-15 नवंबर को राज्य स्तरीय आयोजन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 14 और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती-जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जायेगा। दो दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के आदिवासी नर्तक दल मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। इनमें अरूणाचल प्रदेश के आदि लोक नृत्य नाटिका, मध्यप्रदेश के भील भगोरिया नृत्य, मेघालय के गारो लोक नृत्य और नागालैण्ड के आओ नागा लोक नृत्य सहित विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां होगी।

छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे और पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी एक दिवसीय गौरव दिवस का आयोजन किया जायेगा।

आदिम जाति विभाग द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही हैं। साइंस कॉलेज मैदान में जनजातीय गौरव दिवस के दौरान 14 एवं 15 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक जनजातीय गौरव पर आधारित विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ सहित कई राज्यों के आदिवासी कलाकार, आदिवासी कला संस्कृति के मर्मज्ञ शामिल होंगे।

दो दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को भव्य एवं यादगार बनाने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी नर्तक दलों एवं कलाकारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। अब तक 18 राज्यों के 22 आदिवासी नर्तक दलों ने इस दो दिवसीय आयोजन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है, जिसमें अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के आदिवासी नर्तक दल शामिल हैं। इनमें पुरूष एवं महिला कलाकारों की संख्या लगभग 425 है। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि 14 नवंबर एवं 15 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान में संध्या 3 बजे से अंतर्राज्यीय लोक नर्तक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ जनजातीय गौरव से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन तथा जनजातीय जीवन शैली पर चित्रकला का प्रदर्शन भी होगा।

तीन दिनों तक ट्रेनों का रहेगा परिचालन प्रभावित

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग हेतु रिलीविंग गर्डर की लांचिंग की जाएगी। इस कार्य के लिए दिनांक 15, 16 एवं 17 नवंबर को ट्रैफिक कम पावर ब्लाक लिया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही सड़क मार्ग के उपयोकर्ताओं को सुविधा के साथ ही गाडियों के परिचालन में गतिशीलता आयेगी। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाडिय़ों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द होने वाली गाडियां

15 नवंबर को गाडी संख्या 08728 रायपुर-बिलासपुर मेमू
15 नवंबर को गाडी संख्या 08734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमु
15 नवंबर को गाडी संख्या 08733 गेवरा रोड- बिलासपुर मेमु
15 एवं 16 नवंबर को गाडी संख्या 08719 बिलासपुर-रायपुर मेमू
16 नवंबर को गाडी संख्या 08727 बिलासपुर-रायपुर मेमू
17 नवंबर को गाडी संख्या 08261 बिलासपुर-रायपुर पैसेंजर
17 नवंबर को गाडी संख्या 08275 रायपुर-जूनागढ़ रोड पैसेंजर
18 नवंबरको गाडी संख्या 08276 जूनागढ़- रायपुर रोड पैसेंजर
18 नवंबर को गाडी संख्या 08280 रायपुर-कोरबा पैसेंजर

शिक्षा सचिव परदेशी ने निभाई शिक्षक की भूमिका

विद्यार्थियों को सिखाया कृत्रिम उपग्रह का विज्ञान

रायपुर। स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने महासमुंद जिले के उड़ीसा सीमा से सटे वनांचल क्षेत्रों में स्थित विभिन्न विद्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रों की शैक्षिक प्रगति, स्कूलों की सुविधाओं और शैक्षिक गतिविधियों का गहन अवलोकन किया। बच्चों के उत्साही उत्तरों से प्रभावित होकर श्री परदेशी ने उनकी समझ और ज्ञान की सराहना की।

निरीक्षण के दायरे में आने वाले स्कूलों में हायर सेकेंडरी स्कूल बेलसोंडा, प्राथमिक शाला ओंकारबंद, पीएम श्री स्कूल खोपड़ी, मिडिल एवं हाई स्कूल खोपली, मिडिल और हाई स्कूल कसेकेरा, मिडिल स्कूल कुलिया, और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सुनसुनिया शामिल थे। निरीक्षण के दौरान श्री परदेशी ने कुछ समय के लिए शिक्षक की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों को कृत्रिम उपग्रह के बारे में समझाया। उन्होंने बच्चों से विज्ञान, भूगोल और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे। बच्चों से भारत के महान वैज्ञानिकों, इंद्रधनुष के रंगों की संख्या, छत्तीसगढ़ के जिलों और पड़ोसी राज्यों के बारे में सवाल किए गए, जिनका बच्चों ने सही जवाब दिया। छोटे बच्चों से रंगों और फलों से

जुड़े सवाल भी पूछे गए, जिनमें अधिकांश बच्चों ने सही उत्तर दिए।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सुनसुनिया की छात्राओं ने शिक्षा सचिव से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से रक्षाबंधन पर्व पर हुई मुलाकात का अपना अनुभव साझा किया जिसे छात्रों ने एक अविस्मरणीय पल बताया। इस पर सचिव ने कहा कि आज की बालिकाएं और महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, वे सुई से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। यह समाज में महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। निरीक्षण में शौचालयों की तालाबंदी देखकर श्री परदेशी ने प्रधानपाठक और प्राचार्य को नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि सभी सुविधाएं बच्चों के लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन से प्राप्त सामग्री बच्चों के उपयोग के लिए खुली और उपलब्ध रहनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने शौचालयों में स्वच्छता बनाए रखने और उन्हें स्कूल समय में खुला रखने के निर्देश के साथ ही परिसर की साफ-सफाई, पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग, प्रयोगशाला का उपयोग, शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, शिक्षक डायरी का संधारण और शासन के दिशा-निर्देशों का समयानुसार पालन करने पर भी जोर दिया।

निरीक्षण के अवसर पर रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक श्री राकेश पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत, आलोक चांडक, जिला मिशन समन्वयक श्री कमल नारायण चंद्राकर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

दलों की नाराजगी से 'इंडिया गठबंधन' संकट में

चेतनादित्य आलोक

बागियों की भूमिकाओं, दल-बदलुओं की चालबाजियों तथा विभिन्न दलों के भीतर मची कलह-कुचाल के कारण झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा काफी गर्म है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 05 जनवरी 2025 को समाप्त होगा, लेकिन यहां की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वैसे तो, राज्य में आईएनडीआईए (इंडिया) और एनडीए गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर होने की बातें कही जाती हैं, लेकिन धरातल पर इस बार भी पूर्व की तरह मुख्य चुनावी लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में ही दिखाई पड़ रही है। हालांकि गौरतलब है कि दलों के बीच गठबंधन वाली एकता जैसी एनडीए खेमे में दिखाई पड़ रही है, वैसी एकता आएनडीआइए गठबंधन के खेमे में नहीं है। इसके कारण आएनडीआइए खेमे में मायूसी और चिंता का माहौल बना हुआ है, जबकि दूसरी ओर एनडीए खेमे में निश्चित तौर पर उत्साह और खुशी का माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद दोनों गठबंधनों की ओर से अपनी-अपनी जीत के दावे बेहद जोर-शोर से किए जा रहे हैं। बहरहाल, इस बात का पता तो आगामी 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि चुनाव में किसकी गाड़ी मंजिल तक पहुंचती है और किसकी गाड़ी बीच मजधार में ही फंसी रह जाती है। वैसे खुश होने की एक वजह तो है कि लंबे समय तक नक्सल-प्रभावित रहे झारखंड राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के विश्रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले दिनों यहां पर इंडिया गठबंधन के भीतर खुल कर विरोधी गतिविधियां देखी गईं। गौरतलब है कि सीटों के बंटवारे के बाद विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कोटे में गई थी, जबकि आरजेडी ने विश्रामपुर विधानसभा से जैसे ही अपने उम्मीद्वार रामनरेश सिंह को खड़ा किया, लगे हाथ कांग्रेस ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी यहीं नहीं रूकी, बल्कि उसने विश्रामपुर विधानसभा पर अपना दावा ठोंकते हुए अपने नेता सुधीर कुमार चंद्रवंशी को टिकट थमा दिया। स्थिति यहां तक तक पहुंच गई कि सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने क्षेत्र से नामांकन करके अपने ही अलायंस के पार्टनर प्रत्याशी राजद के रामनरेश सिंह की मुश्किलें बढ़ा दीं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने आरजेडी प्रत्याशी के विश्रामपुर सीट से चुनाव हारने की आशंका के कारण उसने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि यदि राजद प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी से चुनाव हार गए तो आईएनडीआईए गठबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि एक जमाने में विश्रामपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था। हालांकि, पिछले दो चुनावों में उसके प्रत्याशियों को लगातार हार का सामना भी करना पड़ा है, जिससे कांग्रेस का किला पूरी तरह दरकता हुआ दिखाई देने लगा था। वहीं, 2014 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला, जब राजद छोड़कर बीजेपी में आए रामचंद्र चंद्रवंशी ने चुनाव जीता था। फिर उन्होंने 2019 में भी अपनी जीत को भली-भांति दोहराने का कार्य किया। यही कारण है कि पार्टी ने इस बार उन्हें हैट्रिक लगाने की मंशा से मैदान में उतारा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि आएनडीआइए गठबंधन की आपसी कलह समय रहते समाप्त नहीं हुई तो बीजेपी उम्मीद्वार की हैट्रिक लगनी सुनिश्चित है। इसी प्रकार, बीजेपी नेता रवींद्र राय के विद्रोही तेवर के कारण धनवार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे भाजपा के बाबूलाल मरांडी की चुनावी जंग शुरुआती दौर में फंसती दिखाई पड़ने लगी थी, लेकिन बीजेपी ने समय रहते रविन्द्र राय को झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर डैमेज कंट्रोल करने में सफलता पा ली, जिससे बाबूलाल मरांडी का संकट शीघ्र ही टल गया। दूसरी ओर, धनवार विधानसभा सीट पर भी एक बार फिर आएनडीआइए गठबंधन की ही गाड़ी फंसती नजर आने लगी, जब यहां से गठबंधन के दो दो उम्मीदवार आमने-सामने खड़े हो गए। दरअसल, सीट बंटवारे के बाद हिस्से में आई इस सीट पर जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी बाबूलाल मरांडी को चुनौती दे रहे थे, परंतु बाद में सीपीआई के राजकुमार यादव भी धनवार के चुनावी जंग में ताल ठोंकते नजर आने लगे। जाहिर है कि एक ही सीट से एक ही गठबंधन के दो-दो प्रत्याशियों के खड़े हो जाने से आएनडीआइए गठबंधन के वोटों में बिखराव होना तय है और यदि आएनडीआइए गठबंधन ने समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो बाबूलाल मरांडी की विजय बेहद आसान हो जाएगी।

ट्रंप, मोदी, राहुल और चुनाव का फॉर्मूला तीन

शेखर गुप्ता

चुनावी जीत का फॉर्मूला तीन स्तंभों पर टिका है और सफल प्रचार अभियान को उन पर आधारित होना चाहिए। ट्रंप ने इस पर अमल किया। मोदी ने भी 2014 और 2019 में ऐसा किया मगर 2024 में नहीं। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप की जीत हमें क्या बताती है कि नेता ऐसा क्या करते हैं कि वे जीत जाते हैं, हारते हैं या फीकी जीत दर्ज कर पाते हैं। ट्रंप इस बार जीते हैं, राहुल अक्सर हारते रहते हैं और मोदी ने इस बार जून में फीकी जीत हासिल की। तीनों के बारे में सोचिए।

ट्रंप की शानदार जीत से निकला पहला सबक है सफल अभियान के लिए तीन स्तंभों का फॉर्मूला। उसे राष्ट्रवाद, विजयवाद और अविश्वास का नाम देते हैं।

यह कैसे काम करता है, यह जानने के लिए मागा यानी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (अमेरिका को दोबारा महान बनाएं) की अवधारणा पर विचार कीजिए। यानी अमेरिका अभी जितना महान है, उससे अधिक महान बनाने की कोशिश ही राष्ट्रवाद है यानी उसे दोबारा महान बनाया जाएगा। उसे हालिया अतीत की उस स्थिति में लाने, जब वह शीर्ष पर था की बात विजयवाद है। जंग शुरू होने से पहले ही जीत का ऐलान कर दीजिए।

अगर आप दलील देंगे कि अमेरिका पहले से महान था और उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उसका जीडीपी जो 2008 में यूरो क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 50 फीसदी था अब उसके दोगुना हो गया है, उसके शेयरों में तेजी आ रही है, प्रौद्योगिकी और नवाचार में वह दुनिया का नेतृत्व करता है तो मैं आपको बताता हूं अविश्वास क्या है। चुनावी राष्ट्रवाद में मेरा देश तब तक ठीक से महान नहीं होता, जब तक मैं उसकी बागडोर नहीं संभालता। मेरे संभालते ही वह बहुत बेहतर हो जाएगा।

भारत की बात करें तो हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी 2014 और 2019 में बुरी तरह क्यों हारे और मोदी ने शानदार प्रदर्शन क्यों किया। उसके बाद अचानक क्या हुआ, जो 2024 में मोदी अपनी ही नहीं बाजार और चुनाव विश्लेषकों की अपेक्षाओं से भी पिछड़ गए? 240 सीटें उनके लिए निराशाजनक था। दूसरे को चित करने का आदी अगर अंकों के आधार पर जीते तो जीत को खराब ही माना जाएगा। यह क्यों हुआ?

हमारे द्वारा तय तीन बिंदुओं ङ्क राष्ट्रवाद, विजयवाद और अविश्वास की कसौटी पर कांग्रेस और राहुल गांधी की कसना आसान होगा। 2014 में राहुल ऐसी पार्टी के लिए प्रचार

अभियान का नेतृत्व कर रहे थे जो एक दशक से सत्ता में थी। परंतु उनके प्रचार अभियान में शायद ही कभी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। क्या उनकी पार्टी ने एक दशक के कार्यकाल में भारत को महान बनाया? और क्या अब वह उसे और अधिक महान बनाने जा रहे थे? क्या इस दशक ने भारत को सैन्य और कूटनीतिक दृष्टि से अधिक मजबूत तथा रणनीतिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित, वैश्विक रूप से अधिक प्रभावशाली बनाया? क्या कांग्रेस / संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने भारत को उस 'गर्त' से बाहर निकाला जिसमें 'वाजपेयी' की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उसे छोड़ा था? ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए राष्ट्रवाद और विजयवाद का मुद्दा छूट गया।

उनका अभियान ज्यादातर अमीर और गरीब, असमानता, भाजपा की सांप्रदायिकता, उनकी और उनकी पार्टी की गरीबों, वंचित जातियों और आदिवासियों के लिए चिंता पर केंद्रित रहा। राहुल और उनके समर्थक कह सकते थे कि वह सच के करीब रहे क्योंकि उनकी पार्टी के 10 साल के शासन के बाद भी गरीबी, असमानता और अभाव की स्थिति बनी रही। वे कह सकते थे कि इन हालात में वह जीत पर आधारित अभियान कैसे खड़ा कर सकते थे। इसका जवाब हमारी तीन बिंदुओं वाली स्थापना के तीसरे हिस्से में है जो है: अविश्वास।

यह राजनीति है। आप मतदाताओं से बात कर रहे हैं या फिर कहें तो दो तरह के मतदाताओं से। मतदाताओं की एक किस्म वह है जो अनिर्णय में रहती है और आपमें तथा आपके प्रतिद्वंद्वी में बहुत अंतर न कर पाते हुए सभी विकल्पों पर विचार करती है। इससे भी महत्वपूर्ण होते हैं आपके वफादार मतदाता। उन्हें इतना प्रेरित करना जरूरी है कि उन्हें आपकी पार्टी की जीत का यकीन हो जाए और वे बड़ी संख्या में मतदान के लिए आएं।

मतदाताओं का ध्रुवीकरण होने पर ये बातें ही तय करती हैं कि आपको बड़ी चुनावी जीत मिलेगी या सफाया होगा। 2019 में किसी को भी लग सकता था कि कांग्रेस मोदी के पांच साल के कार्यकाल की रिपोर्ट के साथ प्रचार में उतरेगी और दलील देगी कि उसने काफी बेहतर काम किया था और अगर भारत को उसी वैभव पर लाना है तो मतदाताओं को उसे ही वोट देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ।

पूरा चुनाव मोदी सरकार के भ्रष्टाचार (चौकीदार चोर है), कुशासन, नाकाम नोटबंदी और सांप्रदायिकता के आरोपों पर लड़ा गया। पूरा प्रचार अभियान नकारात्मक था। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कांग्रेस के शासन में भारत महान था और उसे दोबारा महान बनाने के लिए वोट दिया जाए। कह सकते हैं कि पुलवामा के बाद मोदी भावनाओं के ज्वार पर सवार थे, जिसने उनकी नाकामियों को ढक दिया। लेकिन हमें यह भी पूछना होगा कि क्या कांग्रेस के अभियान में कहीं राष्ट्रवाद था? जीत की उम्मीद रहने भी दें तो क्या कोई आशावाद भी था?

इससे पहले 2014 में मोदी लगभग उन्हीं विचारों की लहर पर सवार होकर जीते थे, जिन्होंने 2024 में ट्रंप को जीत दिलाई। भारत के सुरक्षा और सशस्त्र बल कमजोर थे और दुनिया उन्हें गंभीरता से नहीं लेती थी। आए दिन आतंकी हमले होते थे और भारत एक थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप अपना दूसरा गाल आगे कर देता था।

ब्रिक्स में उसकी स्थिति कमजोर थी और मोदी भारत को दोबारा महान बनाने का वादा कर रहे थे। उसका 'सोने की चिड़िया' वाला अतीत का वैभव वापस दिलाना चाहते थे, चीन को लाल आंखें दिखाई जानी थीं और पाकिस्तान के लिए तो 56 इंच का सीना था ही।

ये सारी बातें इतनी हावी थीं और कांग्रेस अपने ही विरोधाभासों में इतनी फंसी थी कि वह नया जनादेश चाहती थी लेकिन पिछले दो कार्यकालों को याद नहीं कर रही थी। किसी ने उसे यह याद नहीं दिलाया कि भारत ने उससे पहले वाले दशक में 8 फीसदी की जीडीपी वृद्धि हासिल की थी या फिर उस अवधि में तमाम नए संस्थान बने थे। मोदी भला इन बातों का जिक्र क्यों करते? उन्हें तो कमियां निकालनी थीं। वह तो भारत को दोबारा महान बनाने वाले थे।

तब मोदी 2024 में अपनी ही तार्किक आकांक्षाओं से पीछे क्यों रह गए? सच तो यह है कि उन्होंने अपना प्रचार अभियान बहुत अच्छी तरह से चलाया, जो उपरोक्त तीन बिंदुओं वाले फॉर्मूला पर आधारित था। भारत उनके कार्यकाल में कितना महान बना यह जी20 बैठक के दौरान उनसे गले मिलने के लिए कतार लगाए नेताओं को देखकर जाना जा सकता था। उनके कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर था और आतंकवादी घटनाओं के क्षेत्र में बीते पांच साल, पांच दशकों से बेहतर रहे हैं। अगर वह देश को और महान बनाने का वादा कर रहे हों तो लोग उन्हें वोट क्यों न करते?

अब बात करते हैं उनके अभियान की और उसकी 10 मुख्य बातें लेते हैं। इनमें से तकरीबन सभी कांग्रेस की कही बातों, उसके वादों या जो कुछ कांग्रेस करने को कह रही थी उन पर केंद्रित थीं मसलन- मंगलसूत्र, भैंस, घुसपैठिये, पाकिस्तान से प्रेम, अल्पसंख्यकवाद, जातिवाद, वंचित जातियों के नेताओं के साथ उसका व्यवहार, वंशवाद, भ्रष्टाचार आदि। गिनती और भी लंबी है।

चुनाव की तैयारी के समय उनके पास कई मुद्दे थे जैसे जी20 में बढ़ता वैश्विक कद, महिला आरक्षण, पिछड़ों के लिए राम मंदिर और जाटों तथा पिछड़ों को खुश करने के लिए चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देना। मगर सब कुछ भुला दिया गया। यह मोदी का नया अवतार था जहां वह बचाव करते दिख रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह बात ज्यादा नहीं कही कि कैसे अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत को महान बनाया है और उसे ज्यादा महान बनाने के लिए क्या उन्हें पांच साल और नहीं मिलने चाहिए?

सच यह है कि मोदी अपने विजयी अश्व से उतरकर अखाड़े की लड़ाई में आ गए। इससे अहम राज्यों में उनकी गति भंग हुई। वह विपक्ष के आरोपों का नाराजगी से जवाब देने लगे। इससे पहले ऐसे मामलों में उनका जवाब कुछ यूं होता था कि ये लोग जवाब देने के लिए लायक भी हैं क्या?

यह केवल संदेश में बदलाव नहीं था। 2024 के मोदी उन तीन सूत्रों पर सवार नहीं थे, जिन्होंने उन्हें दो बार बहुमत दिलाया था और जो हाल ही में ट्रंप को सत्ता में वापस लाए हैं। वह केवल उसे बचाने में लगे थे जो उनके पास था। वह इसमें किसी तरह कामयाब हो पाए और इसीलिए 2019 की 303 सीटें 2024 में सिमटकर 240 ही रह गईं।

चुनावी लोकतंत्र में कैसे काम होता है उसका एक तरीका अब तय हो चुका है। अन्य देशों में भी किसी न किसी तरह यही हावी है क्योंकि राष्ट्रीय गौरव, संस्कृति और पहचान की बातें आर्थिक सरोकारों पर हावी हो जाती हैं।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

उपर्युक्त प्रमाणों से यह निश्चित हो जाता है कि वर्तमान वेदसंहिता एं और अष्टादश पुराण-ग्रन्थ श्री वेदव्यास जी ने इस रूप में निबद्ध किये थे तथा इनकी रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा सुप्रबन्ध किया था कि इसी की बदौलत हम इन ग्रन्थों का आज भी दर्शन कर पाते हैं। थो लोग ऐसे परम उपकारी महर्षि के चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के स्थान में मनमानी हाँका करते हैं वे महाकृतघ्न और मनुष्य समाज के शत्रु ही समझे जाने चाहियें।

वर्तमान पुराणों के आदिम वक्ता श्रोता ईश्वरावतार ब्रह्मा जो और मन्त्रद्रष्टा ऋषि वर्तमान पुराणों का उपक्रम और उपसंहार पढ़ने पर अथवा नारद आदि पुराणों में दी हुई पुराणसूची का पारायण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त पुराणों के आदिम ओता या वक्ता ईश्व- रावतार ब्रह्मा जी और मन्त्रद्रष्टा ऋषि लोग हीं हैं, इससे भी उनकी मौलिक सामग्री की प्राचीनता भलीप्रकार विदित हो जाती है। ॅयथा-

ब्रह्मपुराण- ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं भरीचये । (मत्स्य 53 । 13) अर्थात् - ब्रह्मपुराण ब्रह्माजी ने मरीचि के प्रति कथन किया था।

पद्मपुराण- एतदेव यदा पद्म ह्यभूद्वैरण्मयं जगत् । (मत्स्य 53 । 14) अर्थात- पद्मपुराण सृष्टि के आरम्भ में हिरण्यमय पद्मस्थ स्वयम्भू ने ब्रह्मा के प्रति कहा।

विष्णुपुराण- वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः।(मत्स्य 53 । 16) अर्थात् - विष्णुपुराग पराशर ने कहा है। (यही पराशर ऋग्वेद के 6 सूक्तों के द्रष्टा हैं)

शिव-वायु-पुराण- निर्मितं तच्छिवेनैव । (वायु संहिता 6) अर्थात् - शिवपुराण शिव भगवान् ने वायु के प्रति कहा है।

लिङ्गपुराण- प्राह देवो महेश्वरः । (मत्स्य 53 । 36) अर्थात लिङ्गपुराण महेश्वर भगवान् ने कथन किया है। **(क्रमशः)**

गजानन माधव मुक्तिबोध

प्रगतिशील काव्यधारा और समकालीन विचारधारा में भी अत्यंत प्रासंगिक कवियों में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर में हुआ। उनके दादा जलगाँव, महाराष्ट्र के मूल निवासी थे जो ग्वालियर आकर बस गए थे। शमशेर बहादुर सिंह ने बताया है कि उनके किसी पूर्वज ने संभवतः ख़लिजी काल में मुग्धबोध नामक कोई आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था और उसके ही आधार पर उनके परिवार का नाम मुक्तिबोध चल पड़ा। उनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा आदि कई स्थानों पर हुई। बचपन से उनका स्वभाव अंतर्मुखी और आत्मकेंद्री रहा था। वे अत्यंत जिज्ञासु भी थे।

युवा जीवन में कविता और बौद्धिक गतिविधियों के प्रवेश के तुरंत बाद ही उनके जीवन में प्रेम का प्रवेश हुआ।

बक़ौल शमशेर 'एक जनून गहरा और सुंदर और स्थाई।' शांताबाई से स्वेच्छापूर्ण इस विवाह के बाद उनके जीवन में उस संघर्ष और आर्थिक अभाव का प्रवेश हुआ जो अंतिम क्षण तक उनके साथ चलता रहा। मास्टरी, रिपोर्टरी और एडिटरी के मुश्किल दिनों के बाद 1958 में राजनांदगाँव में प्रोफ़ेसरी के दिनों में जीवन कुछ आसान रहा तो 'ब्रह्मराक्षस' और 'अँधेरे में' जैसी महत्त्वपूर्ण कविताओं की रचना की। 1962 में उनके द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तक 'भारतः इतिहास और संस्कृति' को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने से उनके मन को आघात लगा था। जीवन भर साहित्य और साहित्येतर प्रश्नों को लेकर चिंतित रहे मुक्तिबोध 1964 के आरंभ में पक्षाघात के शिकार हुए तो फिर संभल नहीं सके। 11 सितंबर 1964 को अचेतावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई।

47 साल की उनकी अल्पायु में ज़िंदगी का जो रूप रहा, जो रवैया, एटीट्यूड-वह उनकी रचनात्मकता में प्रकट रहा। उन्होंने जिस कठोर यथार्थ को भोगा उसकी अभिव्यक्ति 'फंतासी' या 'फ़ैंटेसी' के शिल्प में की है। 'अँधेरे में' और ब्रह्मराक्षस' सरीखी उनकी लंबी प्रसिद्ध कविताओं सहित अन्य कई कविताओं में कम-बेशी मात्रा में यही शिल्प उतरता हुआ नज़र आता है। हिंदी कविता में फ़ैंटेसी की पहचान मुक्तिबोध से ही होती है। यह फ़ैंटेसी कविता वातावरण के सृजन, वस्तुस्थिति के प्रत्यक्षीकरण, आत्मकथन, बिंब रचना, कर्ता के प्रवेश, काव्यवस्तु और काव्य-कर्ता के बीच संबंध निर्माण और अंतःक्रियाओं के सूत्रों का सृजन, कथ्य का उभार, प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से तय दिशा की ओर प्रस्थान, फ़ैंटेसी से बाहर सचेत वाचक की टिप्पणी आदि प्रक्रियाओं से गुज़रती है जहाँ मुक्तिबोध कोई विशिष्ट क्रम नहीं बनने देते और अलग-अलग कविताओं में बार-बार हेर-फेर से उसे चुनौती देते हैं। बक़ौल नामवर सिंह नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है, जो छायावाद में निराला की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के सामान्य काव्य-मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ ही उनकी सीमा को चुनौती देकर उस सर्जनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया, जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन हो सका।

पूर्वी लद्दाख मसले पर अभी और स्पष्टता जरूरी

अजय शुक्ला

मई और जून 2020 में चीन के सीमा सुरक्षा बल के हजारों जवान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हजारों सैनिक तिब्बत और शिनझियान की हाड़ कंपाती सर्दी से निकले और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लांघकर पांच अलग-अलग इलाकों में भारतीय जमीन पर काबिज हो गए।

उत्तर से दक्षिण तक फैले ये इलाके थे देपसांग का मैदान, गलवान नदी घाटी, गोगरा-हॉट स्प्रिंग, पैंगॉन्ग सो और देमचॉक। चीन से दुनिया भर में कोविड-19 ले जानेवाले कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से रोज की गश्त रोक चुकीं भारतीय टुकड़ियां हैरत में पड़ गईं।

गश्त नहीं होने का फायदा ही चीन ने उठाया और लद्दाख में घुसपैठ कर डाली। जब तक देश की उत्तरी कमान अपने आरक्षित जवानों को लद्दाख भेजकर पीएलए को रोकती बड़ी संख्या में चीनी जवान भारतीय इलाके में घुसपैठ कर चुके थे। उनकी मदद के लिए तोपखाने और टैंक भी पीछे थे।

भारतीय गश्ती दलों को रोकने के लिए चीन के सैनिकों ने हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। 15 जून 2020 को ऐसी ही एक तीखी झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान मारे गए और मारे गए चीनियों की संख्या का तो पता ही नहीं चला। 1975 के बाद पहली बार भारत-चीन सीमा पर झड़प में सैनिकों की जान गई थी। भारत को प्रतिक्रिया देने में समय लगा और 42 टन वजनी टी-90 टैंक समेत तोप आदि को अग्रिम पंक्ति पर भेजा गया जहां उन्हें कई जगह चीन की सेना के सामने तैनात किया गया।

इन बातों को लद्दाख की भौगोलिक स्थिति के

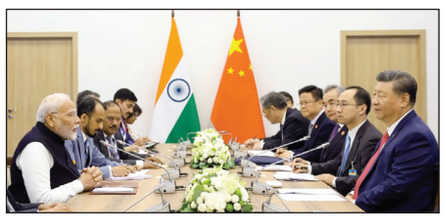

साथ रखकर देखा जाना चाहिए। उस समय अखबारों की सुर्खियों में लिखा जा रहा था कि हिमालय में भारत-चीन आमने सामने हैं। उन्हें नहीं पता था कि जिन चौकियों पर यह घटना हुई थी, वे काराकोरम पर्वत श्रृंखला में थीं, हिमालय में नहीं। इसी तरह लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ तिब्बत पठार पर भारत के कब्जे वाले छोटे से हिस्से पर हुई। उस संघर्ष और झड़प के चार वर्ष बाद तक भारत और चीन कूटनीतिक संवाद में रहे। इसके अलावा दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 21 दौर की बातचीत हुई। सैन्य स्तर पर होने वाली चर्चाओं को ही सेनाओं के पीछे हटने का श्रेय दिया जा रहा है। पहले गलवान घाटी और उसके बाद गोगरा- हॉट स्प्रिंग इलाके से दोनों पक्षों के जवान पीछे हटे। इसके बाद पेगॉन्ग झील के उत्तरी किनारे से सैनिक हटे। बहरहाल, चीन के सैनिक देपसांग और देमचॉक में भारतीय जवानों के सामने अड़े हुए हैं।

अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में भारत का विदेश मंत्रालय यह संकेत देता रहा कि भारत के लगातार दबाव में चीन वह करने को तैयार हो गया है जिसके बारे में वह अब तक चर्चा तक करने से इनकार कर रहा था, यानी-देपसांग और देमचॉक से सैनिकों की वापसी। अगर चीन देपसांग और देमचॉक पर समझौता कर लेता है तो पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद का हल संभव हो जाएगा।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने घोषणा की थी कि बीते कुछ सप्ताहों के दौरान गहन कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं के परिणामस्वरूप एलएसी पर गश्त को लेकर समझौता हुआ है। इसके नतीजे में ही सेनाओं के पीछे हटने और समझौते की घटना घटी।

बहरहाल, भारत ने घोषणा की है कि देपसांग और देमचॉक के लिए चीन-भारत समझौता हो गया है लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय या राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से ऐसा बयान नहीं आया है। गुरुवार 24 अक्टूबर को चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में संकेत दिया कि बातचीत अभी जारी रहेगी। उसने स्वीकार किया कि चीन और भारत मतभेद कम करने और गतिरोध समाप्त करने के लिए सैनिकों को हटाने पर कुछ सहमत हुए हैं। चीन ने कहा कि दोनों देश 'जल्द ही' स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। रविवार 27 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में कहा कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में ही है। उन्होंने कहा, 'हमने फैसला किया है कि अधिक तनाव वाली जगहों पर गश्त नहीं की जाएगी। यानी वर्तमान समझौते के तहत हम अगले चरण पर ध्यान देंगे और बात करेंगे कि सीमा को संभाला कैसे जाए। सारे विवाद हल नहीं हुए हैं लेकिन हम पहले दौर में पहुंच गए हैं।' उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही एलएसी के इलाके में गश्त दोबारा शुरू करेगा।

भारतीय सेना और सरकार से आ रहे वक्तव्यों और घोषणाओं की बात करें तो दोनों में प्रकट आशावाद के स्तर में अंतर है। बेहतर होगा कुछ प्रश्न किए जाएं ताकि इस अंतर को समझा जा सके।

पहला, क्या अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति पूरी तरह बहाल कर दी गई है, खास तौर पर टकराव वाले इलाके देपसांग और देमचॉक में? भारतीय सेना के मुताबिक मंगलवार को सेना के हटने का काम शुरू हुआ और अगले दिन पूरा कर लिया गया। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार इन इलाकों में गश्त अक्टूबर 2024 के आखिर तक शुरू हो जानी थी। देखना होगा कि क्या ऐसा हुआ या फिर जयशंकर की बात ही सही है कि बातचीत अभी प्रारंभिक स्तर पर है। सवाल यह है कि सच क्या है?

दूसरा, सेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जिन इलाकों से पहले ही सेना हट चुकी है और बफर जोन बन चुका है वहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि गलवान, पैन्गॉन्ग सो, पीपी15 और पीपी17ए, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में बफर जोन बने ही हुए हैं। ऐसे में यह दावा कितना सही है कि अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल कर दी गई है क्योंकि उस वक्त तो इन क्षेत्रों में भारतीय सेना गश्त लगाती थी। जाहिर है अब वह स्थिति नहीं रह गई है।

तीसरा, चीन की सरकार ने साफ कहा है कि पीएलए द्वारा पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की एक अहम वजह है भारत द्वारा एलएसी पर बुनियादी ढांचा खास तौर पर दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (डीएस डीबीओ) जैसी अहम सड़कें तैयार करना, जो मध्य लद्दाख में पैंगॉन्ग सो झील के इलाके को काराकोरम दर्रे जैसी सामरिक रूप से अहम जगह से जोड़ती हैं। सरकार को इस अहम प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि क्या उसने बुनियादी ढांचा निर्माण पर किसी रोक को स्वीकार किया है या उन्हें किसी तरह चीन के बुनियादी ढांचा विकास से जोड़ दिया है?

आज का इतिहास

1971 नासा द्वारा भेजा गया यान मैरिनर-9 ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया।
1975 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की।
1979 टाइम्स अखबार पहली बार यूनियनों और प्रबंधन के बीच बहस के एक साल के बाद प्रकाशित किया गया है, कर्मचारियों के स्तर और नई तकनीक की शुरूआत के विषय में।
1982 दक्षिण कोरिया के मुक्केबाज डुक कू किम को लास वेगास के कैसर पैलेस के पास अमेरिकी रे मन्किनी के साथ घातक मस्तिष्क की चोट का सामना करना पड़ा, जिससे खेल में महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन हुए।
1982 वियतनाम के दिग्गज मेमोरियल को वाशिंगटन, डी.सी. में संविधानगार्डन में समर्पित किया गया था।
1985 पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण करीब 23,000 लोग मारे गए थे।
1985 ज्वालामुखी नेवाडो डेल रूइज़ फट गया, जिससे एक ज्वालामुखी बन गया, जिसने अर्मेरो, कोलंबिया के शहर को दफन कर दिया और 23,000 लोगों को मार डाला।
1987 कंडोम के पहले विज्ञापन को ब्रितानी टीवी पर प्रसारित किया गया।
1989 हेंस-एडम द्वितीय, लिकटेनस्टीन के राजकुमार का शासन करते हुए, अपने पिता की मृत्यु का सिंहासन ले लिया।
1989 हंस-एडम द्वितीय, लिकटेनस्टीन के राजकुमार का शासन करते हुए, अपने पिता की मृत्यु पर सिंहासन ले लिया।
1992 ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट ने डिट्रीच बनाम द क्वीन में फैसला सुनाया, हालांकि सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित वकील के पास कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, एक परिस्थिति में एक न्यायाधीश को एक अभियुक्त के रहने के लिए स्थगनकर्ता के लिए कोई अनुरोध देना चाहिए।
1993 फारुख लेगहारी पाकिस्तान के आठवें राष्ट्रपति बने।
1997 सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा प्रतिबंध लगाया।
1997 1993 विश्व व्यापार केंद्र पर बमबारी के मास्टरमाइंडिंग के दोषी रामजी यूसेफ दोषी पाए गए।

'ए.एम.यू.' के अल्पसंख्यक दर्जे पर ऐतिहासिक निर्णय और इसके दूरगामी परिणाम

के.एस. तोमर

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) के अल्पसंख्यक दर्जे पर दिया गया निर्णय न केवल इस संस्थान के लिए, बल्कि व्यापक शैक्षिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह निर्णय, जो विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में दर्जे की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है, कई प्रमुख कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं का समाधान करता है।

निर्णय के बाद, केंद्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को ए.एम.यू. की स्वायत्तता पर अपने दृष्टिकोण की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि यह निर्णय ए.एम.यू. को उसका अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करता है, मगर सरकार नई नियमावली लाने का प्रयास कर सकती है, जो अल्पसंख्यक अधिकारों और अन्य समुदायों के हितों के बीच संतुलन बनाए।

यह निर्णय अन्य संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे पर समान मामलों को उत्पन्न कर सकता है। इसमें वे विश्वविद्यालय भी शामिल हो सकते हैं, जो अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें इस दर्जे से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यह मांग उठ सकती है कि अल्पसंख्यक संस्थान की परिभाषा को स्पष्ट किया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि इन संस्थानों का प्रशासन कैसे किया जाना चाहिए।

हालांकि यह निर्णय ए.एम.यू. के लिए मामला समाप्त कर देता है, लेकिन भविष्य में इसे कानूनी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। भारत में अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जटिल कानूनी और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में कई मामले न्यायालय के इस निर्णय की सीमा का परीक्षण कर सकते हैं। शैक्षिक नीति और अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन पर इसके प्रभावों का विकास जारी रह सकता है।

यह निर्णय सामाजिक और राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है, विशेषकर उन राज्यों में, जहां अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या अधिक है। निर्णय के आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि यह धर्म आधारित विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि इसके समर्थक इसे अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए आवश्यक सुरक्षा के रूप में देख सकते हैं। यह निर्णय शिक्षा में धर्म की भूमिका पर नई बहसों का कारण बन सकता है और यह विचार भी उठ सकता है कि क्या ऐसे संस्थानों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए?

इस निर्णय ने भारत में अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित की है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का बुनियादी अधिकार संरक्षित रहेगा। यह न केवल ए.एम.यू. के लिए, बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

निर्णय ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को विशेष रूप से गैर-सरकारी

संस्थाओं के मामलों में अक्सर चुनौती दी जाती रही है। ए.एम.यू. के अल्पसंख्यक दर्जे की पुनः पुष्टि करके न्यायालय ने इस अनुच्छेद के महत्व को पुनः स्थापित किया है, जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों को संरक्षित करता है।

यह निर्णय विशेष रूप से भारत में सांप्रदायिक संबंधों के संदर्भ में राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है। ए.एम.यू. भारतीय मुस्लिम पहचान, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता के बीच बहस का केंद्र रहा है। यह निर्णय राजनीतिक विमर्श को तेज कर सकता है, जिसमें यह सवाल उठ सकता है कि क्या अल्पसंख्यक संस्थानों को विशेष अधिकार मिलना चाहिए, जबकि शैक्षिक प्रणाली अधिक विविध और प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है।

ए.एम.यू. का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल होना मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए, जो धार्मिक रूप से समायोजित माहौल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। यह समावेशिता की भावना को बढ़ावा दे सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग को उस शैक्षिक अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा जो अन्य समुदायों को इस संस्थान से मिल सकता है।

यह मामला भारतीय उच्च शिक्षा के लिए भी व्यापक निहितार्थ रखता है। यह इस बात पर चर्चा को प्रेरित कर सकता है कि क्या देश भर में समान संस्थानों को समान विशेषाधिकार प्रदान किए जाने चाहिएं? यह अल्पसंख्यक अधिकारों, आरक्षण और शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता पर सरकारी नीतियों के पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया को उत्पन्न कर सकता है।

यह निर्णय पिछले निर्णयों का सीधे तौर पर उत्तर है, विशेष रूप से 1967 में यू.जी.सी. द्वारा ए.एम.यू. का अल्पसंख्यक दर्जा रद्द करने के कदम के खिलाफ। यह निर्णय उन विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सरकारों के हस्तक्षेपों का भी जवाब है, जिन्हें ए.एम.यू. के अल्पसंख्यक चरित्र को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इन लंबित विवादों को निपटाने का प्रयास करता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.), जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में से एक है। इसे मूल रूप से एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय, के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करता है। यह ए.एम.यू. और अन्य समान संस्थाओं की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिससे उनकी स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा होती है। हालांकि, इस फैसले के दूरगामी परिणाम भी हैं, जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने से लेकर अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के भविष्य को आकार देने तक हो सकते हैं। इस फैसले के राजनीतिक और सामाजिक परिणाम आगे भी सामने आते रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा भारतीय शैक्षिक विमर्श में कई सालों तक एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा।

ट्रम्प की जीत का असर वैश्विक मामलों पर भी होगा

कल्याणी शंकर

बहुप्रतीक्षित अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को समाप्त हो गया और पूर्व राष्ट्रपति 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाऊस जीतकर विजय प्राप्त की। यह उनकी दूसरी पारी और एक असाधारण वापसी होगी। वह अमरीका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। ट्रम्प के चुनाव प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं अमरीका में अंतिम वोटों की गिनती से पहले ही आनी शुरू हो गई थीं। इसराईल ने चल रहे बहु-मोर्चे युद्ध से निपटने के लिए उत्साह दिखाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जैसे अन्य लोगों ने चिंता व्यक्त की। इसके विपरीत, अमरीका के कुछ लंबे समय से यूरोपीय सहयोगियों ने चुनाव परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की। यह एक नाखून चबाने वाला इंतजार था। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प चुनावों में लगभग बराबरी पर थे, जिससे सस्पैंस बढ़ गया। संभावना थी कि दौड़ कुछ स्विंग राज्यों तक सीमित हो जाए, जिससे प्रत्याशा और बढ़ गई। ट्रम्प ने कमला हैरिस को हराकर डैमोक्रेट्स को व्हाइट हाऊस से हटाने की कसम खाई। कमला ट्रम्प से हार गईं, ठीक वैसे ही जैसे 2016 में हिलेरी क्लिंटन हार गई थीं। क्लिंटन अपनी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामित पहली महिला थीं। ट्रम्प ने पिछले 20 वर्षों में किसी भी रिपब्लिकन उम्मीदवार की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण मतदाताओं का समूह बनाया, भले ही उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया, जिसमें नस्लीय आरोप लगाए गए और आप्रवासियों पर हमला किया गया था। ट्रम्प का चुनाव न केवल एक राष्ट्रीय, बल्कि एक वैश्विक घटना है। इसका प्रभाव न केवल अमरीकी राजनीति में, बल्कि वैश्विक मामलों में भी महसूस किया जाएगा, विशेष रूप से चल रहे मध्य-पूर्व और यूक्रेनी संघर्षों में। ऐतिहासिक चुनावों ने एक महिला को व्हाइट हाऊस की अध्यक्षता करने का मौका देने से मना कर दिया है। उपराष्ट्रपति चयनित जेडी वेंस का भारतीय संबंध है क्योंकि उनकी पत्नी उषा भारतीय हैं। पिछले 20 वर्षों में, राष्ट्रव्यापी लोकप्रिय वोट जीतने वाले सबसे हालिया रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। यह ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमरीकी चुनाव प्रक्रिया की अनूठी प्रकृति को रेखांकित करता है। 2000 में, उन्होंने इलैक्टोरल कॉलेज और राष्ट्रपति पद जीता लेकिन अलगोर से लोकप्रिय वोट हार गए। डोनाल्ड ट्रम्प 2016 में इलैक्टोरल कॉलेज में 270 से ज्यादा वोट हासिल करके राष्ट्रपति बने थे। यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित संख्या में वोट दिए जाते हैं। हिलेरी क्लिंटन से 2.8 मिलियन से ज्यादा वोटों से लोकप्रिय वोट हारने के बावजूद, प्रमुख राज्यों में ट्रम्प की जीत ने उन्हें जरूरी इलैक्टोरल कॉलेज वोट दिए। 2020 में, ट्रम्प जो बाइडेन से 7 मिलियन से ज्यादा इलैक्टोरल कॉलेज और लोकप्रिय वोटों से हार गए। 2020 के चुनाव के अंतिम नतीजे चार महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों- एरिजोना, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में अनुपस्थित मतपत्र प्रक्रियाओं पर निर्भर थे। ये प्रक्रियाएं, जिन्हें पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं, परिणाम की कुंजी रखती हैं क्योंकि वे मेल द्वारा डाले गए वोटों की वैधता निर्धारित करती हैं। ये युद्ध के मैदान वाले राज्य और उनके अनुपस्थित मतपत्र ही थे, जिन्होंने अंततः ट्रम्प की जीत का फैसला किया। ट्रम्प की जीत के साथ, संभावित हिंसा की आशंकाएं दूर हो गई हैं। जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान होने वाली गड़बड़ी जैसी संभावना कम है। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होने की उम्मीद है, जिससे देश में आश्वासन की भावना आएगी। ट्रम्प 2021 में सुचारू रूप से सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं थे, उनका दावा था कि परिणाम सही नहीं थे और उन्हें शिकार बनाकर धोखा दिया गया था। ट्रम्प की जीत का श्रेय उनके द्वारा संबोधित किए गए विविध मुद्दों को दिया जा सकता है, जैसे कि आव्रजन और अर्थव्यवस्था। इस चुनाव में, ट्रम्प ने न केवल श्वेत वोट हासिल किए, बल्कि मतदाताओं के एक विविध समूह के भी, जो अमरीकी मतदाताओं की जटिलता और विविधता का प्रमाण है।

चुनावी 'नैरेटिव' गढ़ने और निपटने की तैयारी

अमिताभ श्रीवास्तव

यूं तो 'नैरेटिव' अंग्रेजी का शब्द है, जिसका प्रयोग वर्षों से हो रहा है, किंतु पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से यह राजनीतिक शब्दकोष में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। स्थितियां यहां तक हो चली हैं कि राजनेता इसे आम बोलचाल में उपयोग में लाने लगे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में अपनी बड़ी उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद महाराष्ट्र में सत्ताधारी महागठबंधन को हार मानते हुए यह कहना पड़ा कि विपक्ष की ओर से गढ़े गए 'फेक नैरेटिव'(झूठी धारणाओं) ने उसका नुकसान किया। वास्तविक रूप में जो था नहीं, उसे लोगों में फैलाया और विश्वास दिलाया गया।

अब विधानसभा चुनाव में सत्ताधारियों की स्थिति दूध का जला छाछ फूंक-फूंक कर पीने की है। इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (ठाकरे गुट) ने अपने-अपने पासे फेंक दिए हैं। इस बार पहली चाल में यह समझ में आ चुका है कि कोई भी एकतरफा हार स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होगा।

यदि आक्रमण होगा तो उसे उत्तर भी नए पैंतरे के साथ दिया जाएगा। राज्य की उपराजधानी नागपुर से कांग्रेस की 'संविधान सम्मान सम्मेलन' के माध्यम से चुनावी शुरुआत और उसी दौरान सातारा की सभा में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का 'लाल किताब' को लेकर नए विवाद को जन्म देना अचानक या फिर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस ने संविधान बदलने का 'नैरेटिव' चलाकर लोकसभा चुनाव में एक बड़े वर्ग के बीच चिंता का वातावरण तैयार किया था। उसी प्रकार उसने हरियाणा में प्रयास किए। यद्यपि दोनों चुनावों के परिणामों में अंतर था, किंतु कांग्रेस की मतदाताओं के बीच धारणा बनाने की बात सीधी थी। उसने संविधान के ही फार्मूले को झारखंड में आजमाया और अब महाराष्ट्र की बारी है।

हालांकि आम चुनाव में चार सौ पार के नारे और एक उम्मीदवार के संविधान बदलने के बयान ने भाजपा की पांच साल की मेहनत पर पानी फेरा था। बाद में जब वह सीटों के कम होने की परिस्थिति से उबर रही थी कि तभी दो राज्यों के चुनाव आ गए, जहां वह संविधान विषय पर बनाई जा रही धारणा को लेकर अधिक गंभीर नहीं थी,

लेकिन अब झारखंड से जब बात महाराष्ट्र पहुंची तो उसने पूरी तरह निपटने की ठान ली है। कांग्रेस जानती है कि संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र के लिए अधिक संवेदनशील है, जिसके बहाने राज्य के महागठबंधन में विशेष रूप से भाजपा को दबाया जा सकता है। मगर इस बार भाजपा ने सतर्कता दिखाते हुए पहले संविधान की किताब को कोरा बताया और उसके बाद उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने लाल किताब के बहाने 'अर्बन नक्सलवाद' को हवा देने का प्रयास किया है। भाजपा का प्रयास है कि संविधान के 'नैरेटिव' का मुकाबला वामपंथी लाल रंग दिखा कर शहरी नक्सली की संकल्पना को ठोस आधार प्रदान कर किया जाए।

'अर्बन नक्सलवाद' को पूरी तरह भाजपा ने प्रचारित किया है और वह उसे सीमापार के आतंकवाद से जोड़कर देखती है। इसका संदर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधनों में भी आ चुका है। अर्थात? कांग्रेस और भाजपा की 'नैरेटिव लाइन' तैयार है। अन्य दलों में राकांपा (शरद पवार गुट) के मुखिया शरद पवार ने अपनी उम्र का हवाला देकर एक बार फिर सहानुभूति का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। इस बार भी वह स्वयं की चुनावी राजनीति को विश्राम देकर नई पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं। साफ है कि जो समर्थक उनकी बढ़ती उम्र की जिजीविषा को सलाम करते हैं वे उन्हें आगे भी नेतृत्व करते देखना चाहेंगे, जिससे उनके नाम के प्रति सहानुभूति का पोषक वातावरण तैयार होने में कोई समस्या नहीं है।

चुनाव में शिवसेना (ठाकरे गुट) का सारा दारोमदार पार्टी छोड़ने वालों, जिन्हें वह 'गद्दार' कहती है, और निष्ठावानों के बीच है। इसमें भ्रष्टाचार को भी जोड़ा गया है। किंतु पार्टी छोड़ने वाले और भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सीधे तौर पर सामने नहीं आने से निष्ठा और ईमानदारी का 'नैरेटिव' आसानी से गढ़ा नहीं जा सकता है। उसके पास यदि बताने के लिए ढाई साल महागठबंधन सरकार की नाकामियां हैं तो पिछले ढाई साल का शासन उसका भी दर्ज है। इन चार दलों के अलावा शिवसेना(शिंदे गुट) और राकांपा(अजित पवार गुट) हैं, जो किसी सोच और धारणा को खुद बनाने में विश्वास नहीं दिखाते हैं। फिलहाल दोनों ही रक्षात्मक खेल में विश्वास रख रहे हैं। वह सभी आरोपों को खारिज करने और अपने निर्णयों को सही ठहराने में जुटे हैं। उन्हें इस बात का अनुमान है कि उन पर अलग-अलग कोणों से हमले किए जाएंगे, जिनमें उनके सहयोगी भी साथ नहीं देंगे। ताजा प्रकरण पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब में मंत्री छगन भुजबल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बचने के लिए महागठबंधन में जाने का है।

इससे पहले पूर्व मंत्री नवाब मलिक को भी टिकट दिए जाने का मामला आ चुका है। राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक आंदोलनों के 'नैरेटिव' तैयार करने के प्रयास अपनी जगह जारी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), धनगर समाज और मराठा समाज अपनी-अपनी तरह से संदेशों को देकर अपने मतदाताओं के मन-मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहे हैं। कुछ इसी तरह की कोशिशें मुस्लिम संप्रदाय में भी जारी हैं, जो अपने हितों की रक्षा करने वालों को चुनाव में सफल बनाना चाहते हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी राग-द्वेष के होना चाहिए। किंतु वर्तमान समय में यह संभव नहीं दिखाई दे रहा है। पहले इन बातों को गली-मोहल्लों के बीच ही सुना जाता था, लेकिन अब राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें सड़कों से सार्वजनिक मंचों पर ला दिया है। इस कार्य में आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया ने किया है, जिस पर चुनाव के दौरान नियंत्रण लाने की अनेक कोशिशों के बावजूद भी स्थिति अनियंत्रित ही है।

वैसे अब तक किसी धारणा को बनाने की कोशिश एकपक्षीय ही होती आई है। किंतु वर्तमान चुनाव में 'नैरेटिव' से 'नैरेटिव' के मुकाबले की जमीन तैयार हो रही है। देखना यह होगा कि किसकी सोच, किसकी समझ मतदाता के दिमाग पर चढ़ती और मत परिवर्तन करती है। आमने-सामने की लड़ाई में सतर्कता दोनों तरफ है।

झारखंड में सरना कोड पर क्यों बंटे हैं आरएसएस और भाजपा?

अवधेश कुमार

झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासियों से जुड़े मुद्दे शीर्ष पर हैं तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। राज्य की 26.02त्न आबादी जनजातियों की है और 28 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। इनमें से 19 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने पिछले चुनावों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के साथ मिलकर यह आंकड़ा हो गया था 26, भाजपा को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। साफ है, कोई भी पार्टी आदिवासियों के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

सरना कोड यानी सरना विधि संहिता को लेकर राज्य में लंबे समय से विवाद चल रहा है। सरना को अलग धर्म की मान्यता देने और सरना कोड लागू करने की मांग हर चुनाव में उठती रही है। इस बार चुनाव के दौरान ही गोमिया के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाढ़ में 24वां अंतरराष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन होना है। इससे भी मामला गर्म है। इस महासम्मेलन में राज्य और देश के तमाम हिस्सों के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं।

कांग्रेस-जेएमएम ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सरना धर्मकोड लागू करने का वादा किया है। वहीं, भाजपा ने कॉमन सिविल कोड से आदिवासियों को बाहर रखने की घोषणा की है। हालांकि सोरेन सरकार ने सरना को धर्म मानने का प्रस्ताव पहले ही विधानसभा में पारित कर दिया था। तब भाजपा इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब के बयानों से साफ है कि वह भी सरना धर्मकोड लागू करने के पक्ष में है।

भाजपा का मौजूदा रुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके खुद के पहले के स्टैंड से अलग है। संघ और उससे जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम, जनजाति सुरक्षा मंच, विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण मंच ङ्क सभी का कहना रहा है कि आदिवासी चाहे किसी भी समूह के हों, उनकी जाति जो भी हो, वे सभी हिंदू धर्म के ही अंग हैं। सरना अलग धर्म नहीं हो सकता। यह एक पूजा पद्धति है, जो उनकी संस्कृति से जुड़ी है। आज भी इन संगठनों से बात करने पर सीधा उत्तर यही मिलता है कि सरना एक पंथ और संप्रदाय हो सकता है, लेकिन उसे धर्म की मान्यता दे दी तो मूल हिंदू समाज से आदिवासियों को अलग करने का लंबा षड्यंत्र सफल हो जाएगा। केवल संघ ही नहीं, आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले तमाम लोग और खुद आदिवासियों का एक बड़ा तबका भी सरना को अलग धर्म मानने के पक्ष में नहीं रहा है। इनका मानना है कि हिंदू धर्म से अलग होने का भाव उनके भीतर अंग्रेजों ने पैदा किया।

आदिवासियों के लिए यह अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का विषय है। प्रत्यक्ष तौर पर सरना झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों का एक पारंपरिक पूजा स्थल है। ग्रामवासी अपने उत्सवों में यहां जुटते हैं, अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि सरना ग्राम देवता का निवास स्थान है। छोटा नागपुर में गांव के पुजारी को मुंडा और आदिवासियों में पाहान कहते हैं। सहायक पुजारी को देउरी कहा जाता है। पाहान और देउरी जानवरों की बलि देते हैं। स्थानीय आदिवासी इस पवित्र सरना स्थल को जाहेर या जाहिरा या जाहेरथान या जाहिराथान भी कहते हैं। यहां ग्राम देवता, जाहेर बुढ़ी, सिंग बोंगा, बुरु बोंगा आदि की पूजा की जाती है। सिंह बोंगा सूर्य का पर्यायवाची नाम दिखता है।

परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के मामले में विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में अलग-अलग नाम और तरीकों से ऐसे उत्सव व उपासना जगह-जगह होते हैं, जिनके बीच भारी समानता है। अंग्रेजों ने समाज को बांटने के लिए भारत को बहुधर्मी देश घोषित किया। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों के बीच इस भाव को बढ़ाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया।

भारतीय अर्थों में धर्म कभी रिलीजियन का पर्याय नहीं हो सकता। अंग्रेजी शब्द के हिसाब से देखने निकलें तो भारत में इतने ज्यादा पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धतियां और भाषाएं हैं कि हर जिले में कई-कई धर्मों को मान्यता देनी पड़ जाएगी। जिस सरना धर्म महासम्मेलन की हमने चर्चा की, उसका आयोजन सोहराय कुनामी? दिवस पर है, जो वास्तव में कार्तिक पूर्णिमा का ही स्थानीय नाम है।

भारत में अनादिकाल से ग्राम, नगर और वन - तीन प्रकार की जीवन व्यवस्थाएं रही हैं। वनवासियों पर अध्ययन करने वालों ने ऐसे दस्तावेज लाए हैं, जिनमें भूमि के पट्टों से लेकर पुराने पत्रों, अभिलेखों आदि में उन देवताओं के नाम हैं, जो सनातन हिंदू धर्म के हैं। लेकिन, इसे अस्वीकार कर वन के लोगों को हमेशा हिंदू और आम सनातन से अलग बताया गया। झारखंड में गैर आदिवासी भी सरना उत्सव में शामिल होते या अपने गांव में पूजा करते देखे जा सकते हैं।

आम मान्यता यही है कि सरना मूल रूप से आदिवासियों में उरांव जाति का त्योहार है। झारखंड में आदिवासियों में कुल 35 जातियों और उपजातियों की गणना हुई है। हालांकि यह नहीं कह सकते कि यह गणना पूरी है, क्योंकि दूरस्थ जंगलों में कई बार गिनती नहीं हो पाती। अंग्रेजों के समय जनगणना में सरना धर्म कोड का अलग से कॉलम होता था, जिसे 1951 में खत्म कर दिया गया। जिन मान्यता को अंग्रेजों ने समाज को बांटने और राज करने की दृष्टि से वैधानिक बनाया, क्या आज भी उसे जारी रखा जा सकता है? सरना को एक पंथ और संप्रदाय के रूप में अवश्य मान्यता देनी चाहिए और उसकी संहिता भी स्वीकार होनी चाहिए, पर इसे सनातन हिंदू धर्म से अलग मानना भारत की स्वाभाविक सचाई पर आघात होगा।

सपा के गढ़ में तेज प्रताप के लिए चुनौती बने फूफा...

शाहरुख खान

करहल में चुनावी रण सज चुका है। हर प्रत्याशी मानो अपने तरकश के सारे तीर चला देने को आतुर है। सपा के गढ़ में पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव को उनके फूफा अनुजेश सिंह यादव से ही चुनौती मिल रही है। सपा और भाजपा के बीच यहां लड़ाई है तो सिर्फ जीत-हार का अंतर कम करने की। परिणाम क्या रहेगा? चुनाव आयोग 23 नवंबर को बताएगा, लेकिन अधिकतर मतदाताओं के लिए अभी से तस्वीर स्पष्ट है। हम रविवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के रास्ते लखनऊ से ढाई घंटे का सफर तय करके सीधे करहल कस्बे में पहुंचे। कस्बे को दो हिस्सों में बांटती हुई फोरलेन सड़क जहां विकास की गाथा सुना रही है, वहीं स्थानीय बाशिंदों में उससे पैदा हुए आत्मविश्वास की झलक भी मिलती है। यहां मिले विमल चतुर्वेदी काफी मुखर मतदाता हैं। कहते हैं- करहल इस बार गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने की तैयारी कर रहा है। सपा ने अभी भाई को टिकट दिया है, फिर बेटी को यहां से लड़ाएगी। ऐसे तो अन्य लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। प्रवीन राठौर और निजामुद्दीन उनसे (विमल से) इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि यहां इतिहास ही दोहराया जाएगा। वर्ष 2002 के बाद हुए चुनावों में यहां से सपा ही लगातार जीत रही है। 2002 में भाजपा के टिकट पर सोबरन सिंह जीते थे। बाद में सोबरन सपा में आ गए और लगातार तीन चुनाव जीते। 2022 में अखिलेश यादव 67 हजार से ज्यादा मतों से जीतकर करहल से विधानसभा में पहुंचे। उनके सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। करहल के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक माहौल ज्यादा गर्माया हुआ मिला। कुतुकपुर नसीरपुर गांव के बाहर नहर के किनारे पुआल बिछाकर बैठे लोग चर्चा करते हुए मिले। सुमित यादव बताते हैं कि सपा प्रत्याशी तेज प्रताप आम लोगों के साथ संवाद स्थापित नहीं करते, इसलिए उनकी जाति का भी एक हिस्सा भाजपा प्रत्याशी अनुजेश की तरफ जा रहा है। राजकुमार यादव इस बार यादव बिरादरी को कमरिया और घोसी उपजातियों में भी बंटा बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा प्रत्याशी अनुजेश घोसी हैं, इसलिए घोसी उपजाति के यादव उनकी ओर जा रहे हैं। इस बार जीत-हार का अंतर उतना नहीं रहेगा, जितना पहले के चुनावों में रहता था। हरवाई ग्राम के भगवान दास सपा का आधार ही मजबूत मानते हैं। वे एक किस्सा सुनाते हैं कि लड़के की शादी में फूफा जिस तरह से विघ्न डालते हैं, पर उससे विवाह समारोह संपन्न होने से नहीं थमता। ठीक उसी तरह से तेज प्रताप के फूफा अनुजेश चुनाव में उनके लिए विघ्न तो डाल रहे हैं, पर यहां लड़ाई सिर्फ जीत-हार के अंतर को कम करने की है। अपने-अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने की है। हरवाई के ही विष्णु कुमार दुबे मानते हैं कि इस बार करहल विधानसभा क्षेत्र में निजाम बदलना चाहिए। कहते हैं कि वर्ष 2002 में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां से भाजपा जीत सकती है। इस बार भी हवा का रुख भाजपा के पक्ष में ही लग रहा है। ककवाई गांव के अजय कुमार दुबे, राहुल शुक्ला और सत्येंद्र तिवारी भी उनसे सहमत दिखे। कहते हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि जिसकी राज्य में सरकार हो, उसी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो। नगला कूंड के पंकज यादव, अनुजेश को बेहतर प्रत्याशी बताते हैं। कहते हैं कि उन तक अपनी बात पहुंचाना ज्यादा आसान है। नगला डंबर में मिले आनंद कुमार जाटव, रक्षपाल और बैजनाथ बताते हैं कि बसपा यहां मुख्य लड़ाई में शामिल नहीं है। ऐसे में वे अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आनंद कुमार बताते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में उन्हें सपा से कोई परहेज नहीं है। विधानसभा क्षेत्र छोड़ने से पहले करहल कस्बे में चाय की गुमटी पर पेशे से पत्रकार रामकिशोर वर्मा मिलते हैं। वे कहते हैं कि यहां जातीय समीकरण ही अहम है। इस गुणा-भाग में सपा प्रत्याशी ही फिलहाल भारी पड़ते दिख रहे हैं।

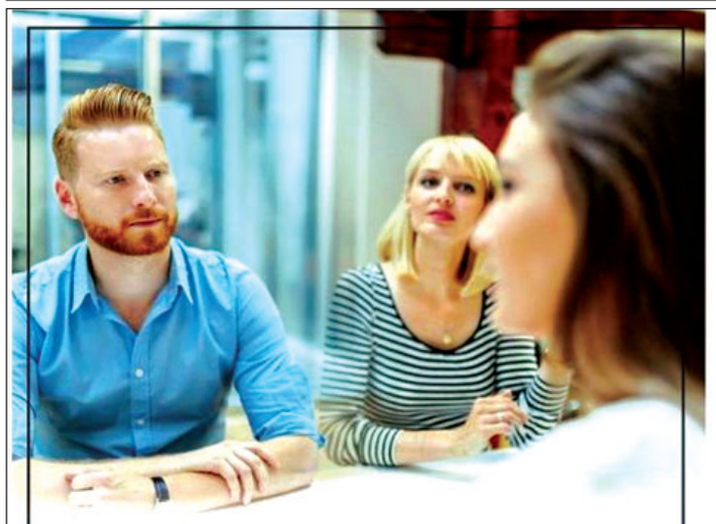

नहीं आया इंटरव्यू के लिए कॉल, आपने की होंगी ये 5 गलतियां

शायद आप कुछ समय से जॉब तलाश रहे हों और आपने अलग-अलग कंपनियों, अलग-अलग पदों पर आवेदन दिया हो। हर दिन आप यह काम करते हो लेकिन आपके पास अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हो, ना कोई कॉल, ना ई-मेल। आपके हताश होने से पहले, यहां कुछ जरूरी बातें दी जा रही है जो कि आप आवदेनों को भेजने के पहले एक बार फरि चेक कर लें।

हर आवेदन में एक ही सीवी और कवर लेटर तो नहीं यूज किया

हर जॉब अलग है और उस जॉब की जरूरत के हिसाब से सीवी में बदलाव की जरूरत होती है। आपको अपना सीवी कस्टमाइज करने के लिए समय निकालना चाहि और यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्या बदलाव किया जाए कि आपको इंटरव्यू के लिए एचआर से कॉल आ जाए। अगर आपका सीवी हर जॉब के हिसाब से पर्सनलाइज्ड नहीं हुआ तो यह इग्नोर हो सकता है। एम्प्लॉयर्स यह बात नोटिस करते है कि आपके सीवी और कवर लेटर में एक ही बातें तो नहीं है। भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप एक अच्छे एम्प्लॉई बन सकते हैं। ऐसी चीजें शामिल करें जिससे कंपनी ज्यादा आकर्षित हो।

आवेदन गलत जगह तो भेज नहीं दिया

जिस व्यक्ति को आवदेन भेजना है उसके नाम में कई आवेदक गलती से या मूर्खतावश गलती कर देते हैं। वशिष रूप से जब आप अलग-अलग जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं तो एड्रेसी और कंपनी का नाम अपडेट करना आसानी से भूल सकते हैं। इतना ही नहीं नाम की स्पेलिंग में गलती भी भारी पड़ सकती है।

आप न्यूनतम योग्यता पर खरे नहीं उतरे हैं

आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा अगर आप अंडरक्वॉलिफाइड हैं। अगर आपके पास आवश्यकतानुसार अनुभव, शैक्षणिक योग्यता नहीं है या आपने उसी माहौल या इंडस्ट्री में काम नहीं किया है तो आपका सीवी बाहर कर दिया जाएगा।

याद रखें, आपको यह पता होना चाहिए कि आप योग्य है लेकिन आप रिक्रूटर के लिए केवल एक कागज का टुकड़ा हैं। वे आपके बारे में उतना ही जानते हैं जो आपका पिछला अनुभव कहता है। उन्हें कई सारे सीवी देखने होते हैं और वे कभी भी अपना समय ऐसे में व्यर्थ नहीं करेंगे या आपके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे।

क्या आप न्यूनतम योग्यता को पार कर गए हैं

अगर आप ओवरक्वॉलिफाइड हैं तो भी आपके पास कॉल नहीं आएगा। कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करेगी। ऐसे में आपका सीवी भी रिजेक्ट हो जाएगा और वे सीवी के ढेर में नए आवेदन पर नजर घुमाएंगे।

कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट किया

भेजने से पहले आपको सीवी आपको बार-बार चेक करना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपने आपका वर्तमान ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर डॉक्यूमेंट्स में अपडेट कर लिया है। अगर आपने आपका पुराना सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिया है तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपने उसे सीवी से भी हटा दिया है। अगर आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में प्राइवेसी सेटिंग कर रखी है तो एचआर को इसके जरिए संपर्क करने का मत कहिए।

भारत में मैनेजमेंट में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के बीच एमबीए इन मार्केटिंग हमेशा से एक लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन रहा है। मगर अब डिजिटल युग के आने से मार्केटिंग के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया है और अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल हो गई है।

अब डिजिटल मार्केटिंग में पा सकते हैं एमबीए डिग्री

पढ़ाई के क्षेत्र के रूप में डिजिटल मार्केटिंग का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा है कि अब मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को एक ही माना जाने लगा है। यूं तो दोनों ही क्षेत्रों में मूल काम उत्पादों व सेवाओं का प्रमोशन तथा सेल्स है मगर डिजिटल मार्केटिंग में अपनाई जाने वाली रणनीतियां परंपरागत मार्केटिंग से बहुत अलग और कहीं अधिक प्रभावी होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र की बढ़ती लोकप्रियता और इसके लगातार विस्तार को देखते हुए मैनेजमेंट गुरुओं ने एमबीए कोर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन की अलग ब्रांच की जरूरत महसूस की। आज डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए का विकल्प तो उपलब्ध है मगर कई विद्यार्थियों में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है और वे इन दोनों में से किस स्पेशलाइजेशन का चयन करें। तो चलिए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अलग

जहां 'मार्केटिंग'' में सभी प्रकार की मार्केटिंग आती है, वहीं 'डिजिटल मार्केटिंग'' में केवल डिजिटल माध्यमों द्वारा की गई मार्केटिंग शामिल है। इनमें वेबसाइट, सोशल नेटवर्क, बैनर ऐड, गूगल ऐड, सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियो आदि आते हैं। परंपरागत मार्केटिंग में विज्ञापनदाता से उपभोक्ता की ओर सूचना का एकतरफा प्रवाह होता है। वहीं डिजिटल माकेटिंग में दोतरफा संवाद संभव है। परंपरागत मार्केटिंग में जहां विज्ञापन की लागत बहुत अधक आती है, वहीं डिजिटल मार्केटिंग में यह कम रहती है। परंपरागत मार्केटिंग कैंपेन काफी पहले से प्लान किए जाते हैं मगर डिजिटल कैंपेन तात्कालिक भी हो सकते हैं।

एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग

कई युवाओं का तर्क होता है कि केवल डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए कर अपनी पढ़ाई का स्कोप सीमित करने के बजाय मार्केटिंग में एमबीए करना बेहतर है। यह बात अपनी जगह सही हो सकती है मगर आप जरा डिजिटल मार्केटिंग को भविष्य के नजरिये से भी देखें। पिछले एक दशक में सारे बिजनेस घरानों ने अपना ध्यान मार्केटिंग के परंपरागत माध्यमों से हटाकर डिजिटल माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग की लोकप्रियता के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख हैं कम लागत, तत्काल प्रतिसाद, लचीलापन, सुविधा और प्रभावशीलता। कई जानकार तो यह भी कहते हैं कि आज के दौर में अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग नहीं की, तो ग्राहक आपसे दूर ही रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में सारी मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर ही जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर खास तरह की मैनेजमेंट स्किल की जरूरत होती है। इसीलिए एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतर तथा आकर्षक करियर ऑप्शन बन गया है।

क्या है स्कोप

हमारे यहां अब भी यह फील्ड अपने शुरूआती दौर में है और इसके बड़ी तेजी से विस्तार लेने की उम्मीद है। डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए के विद्यार्थियों को तकनीकी बुनियाद तथा डिजिटल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स से रूबरू कराया जाता है। इसमें ये विषय भी शामिल होते हैं : वेब एनालिटिक्स, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, बायर बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बी2बी ई-मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आदि। भविष्य में इनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजिन मार्केटिंग आदि के भी शामिल किए जाने की संभावना है।

पे-पैकेज

काफी नई फील्ड होने के बावजूद डिजिटल मार्केटिंग वेतन के लिहाज से बेहद आकर्षक है। एक नया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 4 से 5 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज पा सकता है। अनुभव के साथ इसमें तीव्रता से वृद्धि होती है। 5 से 7 साल का अनुभवी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 10-12 लाख का वार्षिक पैकेज पा सकता है।

करियर ऑप्शन

डिजिटल मार्केटिंग में डिग्री लेने के बाद करियर के कई ऑप्शन खुले होते हैं। फिलहाल हम इनमें से 3 सबसे बेहतर ऑप्शंस की चर्चा करेंगे।

डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर

इन्हें मार्केटिंग की भाषा में 'बज क्रिएटर'' भी कहा जाता है। ये कस्टमर बिहेवियर डेटा पर काम करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग की ऐसी रणनीति तैयार करते हैं, जिससे उस उत्पाद या सेवा के प्रति उपभोक्ता की जिज्ञासा जागे। ईमेल मार्केटिंग, ईकॉमर्स, सोशल मीडिया कैंपेन आदि इनके काम का हिस्सा हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में जॉब के अवसर अकेले इस साल ही 12 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कोडिंग, वेब डिजाइन, एप्लिकेशन डेवलपमेंट, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स तथा जनरल मैनेजेरियल एप्टिट्यूड में पारंगत हो जाएं।

इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर

अगर आपमें डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग का हुनर है, तो आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर को मुख्य रूप से मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम करना होता है। वे कस्टमर बिहेवियर डेटा का अध्ययन कर यह तय करते हैं कि उत्पाद या सेवा की बिक्री की कितना संभावना है। इसमें एमबीए की डिग्री के अलावा मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस में सर्टिफिकेशन आपके काम आएगा।

डिजिटल सेल्स मैनेजर

मार्केटिंग व सेल्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो कई कंपनियां डिजिटल सेल्स की जिम्मेदारी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल को सौंपती हैं। यदि आपको डिजिटल मीडिया व निजता कानूनों, ब्राण्ड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आदि का ज्ञान है, तो डिजिटल सेल्स मैनेजर के रूप में यह आपको बहुत काम आएगा।

साइंस स्टूडेंट्स के लिए इस क्षेत्र में ढेरों हैं संभावनाएं

विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए दिन नई-नई शाखाएं जुड़ रही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी भी तुलनात्मक रूप से एक नया क्षेत्र है। नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देश-विदेश में छलांगें लगाकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को 'साइंस ऑफ मिनिएचर' अर्थात लघुतर का विज्ञान भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु या सामग्री नैनो डाइमेंशन (10-9 मीटर = 1 नैनोमीटर) में बदल जाती है, तो उसके भौतिक, रासायनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय, यांत्रिक और इलेक्ट्रिक गुणों में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय क्षेत्र है, जिसमें नए अवसरों की भरमार है। नैनो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों को व्यावहारिक सीमाओं से परे जाकर आणविक स्तर पर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।

हर क्षेत्र में पैठ

नैनो टेक्नोलॉजी वर्तमान में मानवीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। यह तकनीक बायोसाइंस, मेडिकल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, सिक्योरिटी, फैब्रिक्स और विविध क्षेत्रों में चमत्कार कर रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नैनो टेक्नोलॉजी प्रत्येक क्षेत्र जैसे मेडिसिन, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग, विभिन्न उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। कुल मिलाकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, जो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा।

आर एंड डी पर आधारित

आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी के फायदों को देखते हुए पूरे विश्व में अकादमिक स्तर पर इसे एक विषय के रूप में अपनाया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हमारे देश में उपलब्ध हैं। एमटेक और एमएससी कोर्स में प्रवेश के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन आदि विषयों से ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है।

नैनो टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम का स्वरूप मूलत: रिसर्च एवं डेवलपमेंट (आर एंड डी) पर आधारित होता है। इसके पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को पहले संबंधति विषय के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है। इसके बाद इस तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के अनुरूप अप्लाइड रूप देकर अन्य विषयों की जानकारी दी जाती है, ताकि पाठ्यक्रम रोचक, वस्तुनिष्ठ व ज्ञान पर आधारित बन सके। इसमें पदार्थ के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों का सूक्ष्मतम अध्ययन कराया जाता है। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में क्वांटम थ्योरी, लिथोग्राफी, कार्बनिक और अकार्बनिक नैनो मटेरियल, स्पेक्ट्रोग्राफी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, रमन प्रभाव, नैनो बायोसाइंस, जीन स्ट्रक्चर आदि शामिल हैं।

करियर के कई विकल्प

नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन करने वालों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में करियर के अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। यह तकनीक रक्षा, सैन्य सामग्री निर्माण, फॉरेंसिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है। नैनो टेक्नोलॉजी पर्यावरण, कृषि, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार प्रदान करती है। इस तकनीक का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में यह तकनीक अच्छी करियर की संभावनाएं रखती है। नैनो टेक्नोलॉजी के अध्यापन के क्षेत्र में भी करियर बनाया जा सकता है।

खुल रहे हैं नए द्वार

नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न तत्वों की बॉण्ड संरचना में परिवर्तन करने पर या उनका आपस में संयोग करने पर एकदम नए तत्व का निर्माण भी किया जा सकता है। इस विषय में अभी बहुत-से नए आयाम खोजे जाने बाकी हैं तथा इसके प्रयोग से भौतिकी के लगभग सभी सिद्धांतों को यथार्थ रूप दे पाना संभव हो सकता है। इसलिए यह विषय शोधर्थियों के लिए कार्यक्षेत्रों के नए द्वार खोलता है। इस टेक्नोलॉजी को और भी उन्नात बनाने तथा भविष्य में इस क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए भारत सरकार भी पहल कर रही है। अमेरिका का नेशनल साइंस फाउंडेशन 'नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव' नामक योजना चला रहा है। इसके साथ ही विश्व के तमाम उन्नत देश भी इस पर अलग-अलग नामों से योजनाएं चला रहे हैं। अनेक देश इस विषय में शोध के लिए प्रतिवर्ष अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इसके चलते इस क्षेत्र में जॉब्स के भरपूर अवसर निर्मित होने जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को आज जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे हैं शिक्षित, प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों की कमी। नैनो टेक्नोलॉजी विभिन्न प्रमुख नवाचारों के विकास में संलग्न है और इस क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे कुशल मानवशक्ति को रोजगार के उजले अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

प्रमुख संस्थान

- आईआईटी, दिल्ली
- आईआईटी, गुवाहाटी
- आईआईटी, कानपुर
- जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरू
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरू
- नेशनल केमिकल लैबोरेट्री, पुणे
- एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र

मुंबई। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। यह घोषणा पत्र आम आदमी के विचारों को ध्यान में रखते हुए और उसकी प्रगति की चिंता करते हुए बनाया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए कई वादे इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में प्यारी बहन योजना के तहत दी जाने वाली 1500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया है। यानी हर महिला के खाते में लगभग 25 हजार रुपये हर साल जमा होंगे। इसके अलावा भी किसान सम्मान योजना के तहत हर किसान भाई को वर्तमान वार्षिक 12 हजार रुपये की जगह पंद्रह हजार रुपये देने का वादा भाजपा ने किया है। हर गरीब का सपना पूरा होगा ऐसा आश्वासन इस घोषणा पत्र में दिया गया है। वृद्ध पेंशन धारकों को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा भाजपा ने किया है।

भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कांग्रेस का पलटवार

नईदिल्ली। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे पर कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने कहा कि उनका एक ही एजेंडा है। 2024 के चुनाव में उन्होंने क्या किया? मंगलसूत्र, भैंस, क्या-क्या नहीं कहा उन्होंने? उन्हें बस एक ही बात पता है। जब चुनाव आते हैं और प्रचार शुरू होता है, तो वे केवल ध्रुवीकरण करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। कथा सामाजिक मुद्दों, या किसानों, महिलाओं, युवाओं, एससी, एसटी और ओबीसी के मुद्दों के बारे में नहीं है बल्कि केवल सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में है। तो, यह उनका एकमात्र एजेंडा है। भाजपा द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाने पर रमेश ने कहा कि इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। वे जल, ज़मीन, जंगल के बारे में क्यों नहीं बोलते? 5 वर्षों में हमारी सरकार की उपलब्धि की आलोचना करें। संख्याओं के बारे में बोलें। यदि आप सत्ता में निर्वाचित हो गए

केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली आप नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत का आदेश, जिसे केजरीवाल ने चुनौती दी है, दो महीने पुराना है और कोई नया आदेश नहीं है। उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में एजेंसी द्वारा दायर शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत की स्थिरता पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जबकि शिकायत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दायर की गई थी।

आजम के घर पहुंचकर अखिलेश ने उनकी पत्नी से की मुलाकात

लखनऊ। कभी हिन्दू वोटों के लिये आजम से दूरी और कभी मुस्लिम वोटों के लिये आजम से करीबी बना लेना समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का सियासी खेल बन गया है। इसी के चलते अखिलेश ने जेल में बंद पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ हैं। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि आजम खान को कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और सपा की सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठे मामले खत्म कर दिए जाएंगे। यादव रामपुर से पार्टी के लोकसभा सदस्य मोहिबुल्लाह के साथ आजम के घर पहुंचे तथा उनकी पत्नी तजीन फातिमा और परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक भाजपा दिल्ली और लखनऊ की सत्ता से नहीं हट जाती तब तक संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी।

नाना पटोले के बयान पर किरीट सोमैया ने किया पलटवार

मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने अकोला जिले में एक चुनावी रैली के दौरान विवाद खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं, भाजपा ने भी कांग्रेस नेता पर कड़ा प्रहार किया और उन्हें कुंठित आदमी कहा। पटोले ने अपने संबोधन के दौरान कहा मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप- अकोला जिले के ओबीसी, बीजेपी को वोट देंगे जो आपको कुत्ता कहती है?...यह बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय है। कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि वे निराशा से हताशा की ओर जा रहे हैं। शरद पवार कुछ कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे मौखिक रूप से चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं। अब, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कह रही है क्योंकि सर्वेक्षणों में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, इसलिए मैं उनकी निराशा को समझ सकता हूं।

चिमूर में बोले मोदी- अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी

■ **महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री**

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं, ये आप लोगों ने आज ही दिखा दिया है। ये जनसैलाब बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि चिमूर की जनता ने और पूरे महाराष्ट्र ने ठान लिया है- भाजपा- महायुती आहे, तर गती आहे। महाराष्ट्राची प्रगती आहे। उन्होंने कहा कि मैं आज महाराष्ट्र भाजपा को भी बधाई दूंगा, जिसने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई-बहनों के लिए, युवाशक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए हैं।

मोदी ने कहा कि महायुति के साथ-साथ केंद्र में एनडीए की सरकार यानी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, यानी विकास की डबल रफ्तार। महाराष्ट्र के लोगों पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है, जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। यहां नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब एक दर्जन वंदे भारत ट्रेन चल रही है, यहां के 100 से ज्यादा स्टेशनों के कायाकल्प किया जा रहा है, कई रेलमार्गों का विस्तार हो रहा है।

भाजपा नेता ने कहा कि महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अघाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का तेज विकास, अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर

ब्रेक लगाने में ही पीएचडी की है। कामों को अटकाने, लटकाने और भटकाने में कांग्रेस वाले तो डबल पीएचडी हैं। 2.5 साल में इन्होने मेट्रो से लेकर, वधावन पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजना को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिए अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाडी!

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा जम्मू-कश्मीर दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा। महाराष्ट्र के कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू-कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370। ये धारा 370 कांग्रेस की देन थी। उन्होंने कहा कि हमने 370 को खत्म किया। कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। यहां नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। हिंसा का खूनी खेल चलता रहा, औधोगिक संभावनाओं ने यहां दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। आज ये पूरा क्षेत्र खुलकर सांस ले पा रहा है। अब चिमूर और गढ़चिरौली के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। इस क्षेत्र में नक्सलवाद फिर से हावी न हो जाए, इसके लिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों को यहां फटकने भी नहीं देना है।

मोदी ने कहा कि भाजपा और महायुति सरकार सबका साथ-सबका विकास के मंत्र को लेकर काम कर रही है। मैं गरीब के जीवन की मुश्किलों को समझता हूं, इसलिए आपका जीवन आसान बनाने के लिए मैं दिनरात काम करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है। आज यहां किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। महायुति सरकार साथ में नमो शेतकरी योजना का डबल फायदा भी दे रही है।

उन्होंने कहा कि आज मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूं। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10त्न के आसपास है। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में अपनी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए। उन्होंने कहा कि आपकी एकता टूट जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। आदिवासी समाज जातियों में बटेगा, तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है।

उन्होंने कहा कि अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार की हमेशा से मानसिकता रही है कि वो इस देश वे राज करने के लिए ही पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया।

राहुल गांधी ने चिखली के मतदाताओं से मांगी माफी

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के चिखली के मतदाताओं से माफी मांगी। दरअसल, गांधी की एक सार्वजनिक रैली होने वाली थी, लेकिन सुबह उनके विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वह नहीं आ सके। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गांधी को माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा चिखली (महाराष्ट्र) आने का कार्यक्रम था लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण मैं मंगलवार सुबह वहां नहीं आ सका। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मेरी आज एक सार्वजनिक रैली करने और सोयाबीन किसानों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम था। सोयाबीन और कपास किसानों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। मुझे पता है कि भाजपा इन किसानों को सही कीमत नहीं देती है। जैसे ही भारत गठबंधन की सरकार बनेगी सत्ता में आने पर हम आपके लिए समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। महा विकास अघाड़ी गठबंधन, जिसका हिस्सा कांग्रेस है, ने किसानों के लिए 3 लाख तक की कर्ज माफी और नियमित ऋण भुगतान के लिए 50,000 रुपये प्रोत्साहन का वादा किया है।

गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि मौजूदा योजनाओं में सुधार करने और किसानों की आत्महत्या से प्रभावित परिवारों की विधवाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा की जाएगी।

झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस पर बरसे अमित शाह

रांची। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के झरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के महान नेता मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि है। मालवीय जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया और साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। मैं आज मालवीय जी को प्रणाम करके आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने लोगों से कहा कि आने वाली 20 तारीख को आप सभी को वोट देना है। आपका एक एक वोट झारखंड का भविष्य तय करने वाला है।

शाह ने साफ तौर पर कहा कि आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति-अरबपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए, या गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेन्द्र मोदी की सरकार आपको चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं से करोडों रुपये पकड़े गए हैं, ये सारे पैसे झरिया और धनबाद के युवाओं और माताओं-बहनों के हैं। आप भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम इन करोडों रुपये लूटने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग का और युवाओं का जो रुपया उन्होंने लुटा है, उसकी पाई-पाई उनसे वसूल करके

झारखंड की तिजोरी में जमा की जाएगी।

कांग्रेस और जेएमएम पर हमला जारी रखते हुए शाह ने कहा कि इन्होंने ने 1 हजार करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, भूमि घोटाला किया, खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। ये घोटाला करने वाली सरकार है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा खटाखट-खटाखट घोषणाएं करते हैं, जो पूरी नहीं होती। अब आप भी ना बोल रहे हैं और राहुल बाबा की पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी भी कह रहे हैं कि कुछ पूरा नहीं होने वाला। लेकिन मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर होती है। एक-एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे। शाह ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है। ये देश के पिछड़ों, दलितों का आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिये, जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उनका (जेएमएम-कांग्रेस) मानना है कि उन्होंने जनता का पैसा लूट लिया है और कुछ नहीं होगा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत को अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

सेंचुरियन। भारतीय बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को सेंचुरियन में होने वाले तीसरे टी20 मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी जो पिछले मैच में पूरी तरह नाकाम रहे थे। भारत ने 2009 के बाद से यहां पर सिर्फ एक टी20 मैच खेला है और 2018 में खेले गए इस मैच में उसे छह विकेट से पराजय मिली थी। उस टीम का एक ही सदस्य हार्दिक पंड्या मौजूदा टीम में है। भारत की चिंता का सबब उसके बल्लेबाजों का खराब फॉर्म भी है चूंकि सुपरस्पोर्ट पार्क की पिच भी गबेरहा की पिच की ही तरह तेज और उछाल भरी है। दूसरे टी20 में भारतीय बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने काफी परेशान किया था और भारतीय टीम छह विकेट पर 124 रन ही बना सकी थी।

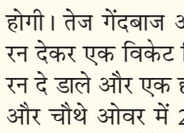

शीर्षक्रम में अभिषेक शर्मा लगातार नाकाम रहे हैं और इससे पहले कि टीम प्रबंधन संयोजन में बदलाव की सोचे, उन्हें अच्छी पारी खेलनी होगी। अभी भी संजू सैमसन के साथ पारी की शुरूआत करने तिलक वर्मा को उतारा जा सकता है जिससे रमनदीप सिंह मध्यक्रम में उतर सकते हैं। सीनियर बल्लेबाज कप्तान सूर्यकुमार यादव, पंड्या और रिंकू सिंह को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

सूर्यकुमार और रिंकू लय में नहीं है जबकि पंड्या ने दूसरे मैच में 39 रन बनाने के लिये 45 गेंदें खेल डाली। उन्हें पहला चौका जड़ने के लिये 28 गेंद तक इंतजार करना पड़ा। इन तीनों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा जबकि सैमसन को पिछले मैच की नाकामी भुलाकर बड़ी पारी खेलनी होगी। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने डरबन में 25 रन देकर एक विकेट लिया लेकिन दूसरे मैच में 41 रन दे डाले और एक ही विकेट मिला। उन्होंने तीसरे और चौथे ओवर में 28 रन दे डाले जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स ने चार चौके लगाये। उन्हें भी अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा अन्यथा यश दयाल या विशाख विजयकुमार को मौका मिल सकता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 820 अंक लुढ़का निफ्टी 23,900 के नीचे बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में गिरावट के रुख के बीच भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की लगातार जारी बिकवाली और कंपनियों के कमजोरी तिमाही नतीजों ने निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज पॉजिटिव नोट के साथ 79,644.95 अंक पर खुला। हालांकि, सेंसेक्स ज्यादा देर तक तेजी को संभाल नहीं सका और अंत में 1.03त्न या 820.97 अंक की बड़ी गिरावट लेकर 78,675.18 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 1.2 प्रतिशत या -288.80 अंक की गिरावट के साथ 23,852.50 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में एनटीपीसी का शेयर सबसे ज्यादा 3.16 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ।

भारत-रूस के बीच होगा 100 अरब डॉलर का व्यापार

नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक तकनीक मामलों के अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। वहीं रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव कर रहे हैं। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2030 तक बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाएगा। एस जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। रूस भारत के लिए फर्टिलाइजर, कच्चे तेल, कोयला और यूरेनियम का मुख्य स्त्रोत बनकर उभरा है। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच व्यापार साल 2030 तक या उससे भी पहले, 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला पावर पीएसयू से अल्ट्रा मेगा ऑर्डर

नईदिल्ली। सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) की बिजनेस वर्टिकल एलएंडटी एनर्जी कार्बनलाइट सॉल्यूशंस को पावर पीएसयू एनटीपीसी से अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर मध्य प्रदेश और बिहार में थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए है। अल्ट्रा मेगा ऑर्डर की खबर में एलएंडटी के शेयर में मूवमेंट देखने को मिला। दिग्गज कंस्ट्रक्शन स्टॉक की चाल देखें तो बीते एक साल में यह करीब 20 फीसदी उछला है। एलएंडटी ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि एलएंडटी एनर्जी कार्बनलाइट सॉल्यूशंस को एनटीपीसी लिमिटेड से बिहार और मध्य प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 15000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऑर्डर मिला है. इस ऑर्डर के अंतर्गत कंपनी को मध्य प्रदेश के गाडरवारा में 2×800 मेगावाट स्टेज- II थर्मल पावर प्लांट और बिहार के नबीनगर में 3×800 मेगावाट स्टेज-II थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए मिला है।

गोल्ड ईटीएफ में लोग जमकर लगा रहे पैसा!

नईदिल्ली। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बीच घरेलू स्तर पर गोल्ड ईटीएफ में पिछले महीने यानी अक्टूबर के दौरान निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। गोल्ड ईटीएफ को लेकर निवेशकों के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल अप्रैल को छोड़कर बाकी 9 महीनों के दौरान गोल्ड ईटीएफ में निवेश यानी इनफ्लो बढ़ा है। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 18 गोल्ड ईटीएफ में अक्टूबर 2024 के दौरान 1,961.57 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 133 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान देश के कुल 13 गोल्ड ईटीएफ में महज 841.23 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था। पिछले महीने यानी सितंबर के मुकाबले देखें तो इसमें 59 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

भारत-चीन : भू-राजनीति अर्थशास्त्र से दूर नहीं रह सकती

जितेंद्र उत्तम

नेपाल व भारत के बीच मानचित्र संबंधी युद्ध और चीन व भारत के बीच लंबित सीमा विवाद से उत्पन्न भू-राजनीतिक गतिरोध ने भू-आर्थिक संबंधों के विचारों को गति दी है। भू-राजनीति की प्रधानता ने शीतयुद्ध के बाद अंतर-एशियाई व्यापार और निवेश में वृद्धि द्वारा पोषित गति को पटरी से उतार दिया था। हालांकि, वाशिंगटन के साथ बीजिंग की बढ़ती कलह, वैश्विक दक्षिण का उदय और ब्रिक्स की सफलता ने चीन को भू-राजनीतिक मुद्दों पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया है।

पड़ोसी देशों के साथ भू-राजनीतिक झगड़ों के प्रति अपने रवैये में चीन बदलाव का अनुभव कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ मानचित्र विवाद से लाभ उठाने की नेपाल की रणनीति काम नहीं कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संभालने के अपने रवैये में बदलाव के तहत चीन ने अप्रत्याशित रूप से भारत से सीमा समझौता किया है। ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र आखिरकार चीन-भारत संबंधों को प्रभावित करने वाली राजनीतिक समस्याओं का समाधान पेश कर रहा है।

भू-आर्थिक झुकाव पहले ही अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। चीन वर्ष 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। यह असाधारण उपलब्धि तब मिली, जब दोनों देश खूनी सीमा संघर्ष में उलझे थे और भारत ने 220 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अधिक आत्मनिर्भरता और बीजिंग के साथ व्यापार पर अंकुश लगाने के बावजूद भारत अब भी चीनी वस्तुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। दोनों देशों के बीच मांग-आपूर्ति का बहुत

बड़ा खिंचाव है और राजनीति के लिए इसे नजर अंदाज करना मुश्किल है।

गलवां की घटना के बाद सैन्य तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भारत ने चीनी निवेश को सीमित कर दिया था। हालांकि, भू-आर्थिक निर्देशों का पालन करते हुए भारत ने कुछ चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो चीन के प्रति भारत के आर्थिक रुख में बदलाव का संकेत है। इससे पता चलता है कि भू-राजनीतिक तनाव अस्थायी रूप से भू-आर्थिक संबंधों को पटरी से उतार सकते हैं, पर उन्हें लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकते।

इसे दो कारणों से समझा जा सकता है कि चीन अचानक भू-अर्थशास्त्र की ओर क्यों मुड़ रहा है। पहला, यह कि बड़े पैमाने पर उत्पादित चीनी वस्तुओं के प्रति पश्चिम में रुचि घट रही है। ट्रंप प्रशासन ने लगभग 300 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर व्यापक टैरिफ लगाया था। राष्ट्रपति जो बाइडन ने न केवल उस टैरिफ को बरकरार रखा, बल्कि लगभग 15 अरब डॉलर के चीनी आयात पर कुछ टैरिफ दरों को बढ़ाने का फैसला किया। यूरोपीय देशों ने भी चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर 45 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने पर अमेरिका का अनुसरण किया।

दूसरा, यह स्पष्ट संकेत है कि ग्लोबल साउथ पश्चिमी प्रभाव से बाहर निकल रहा है। लगता है कि चीन महान शक्ति के रूप में अपनी नई-नई स्थिति से बहक गया है, और अपनी कथित शांतिपूर्ण वृद्धि की परिकल्पना से बाहर नीतिगत मामलों में मुखर हो रहा है। चीन अक्सर भारत सहित कई पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय विवादों को उकसाता है। पश्चिम ने चीन की धमकियों का इस्तेमाल एक नए भू-राजनीतिक मंच का आधार बनाने के लिए किया, जो बीजिंग के अनियंत्रित व्यवहार का मुकाबला कर सके। एक नया भू-राजनीतिक समूह हिंद-प्रशांत 'चीन को रोकने' के लिए समर्थन जुटाने की खातिर सामने आया। अचानक, चीन विरोधी बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया और कई देश बीजिंग को सबक सिखाने के लिए 'सैन्य गठबंधन' की बात करने लगे। इन सबने चीन के निर्यातोन्मुखी विकास मॉडल को कमजोर करना शुरू कर दिया, जिसके विनिर्माण उद्योगों को पश्चिमी बाजारों की जरूरत है। उधर संयुक्त पश्चिम ने चीनी वस्तुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का कदम उठाया।

रायपुर दक्षिण के 2 लाख 71 हजार मतदाता चुनेंगे अपना विधायक

आज मतदान, तैयारियां पूरी, प्रशासन व राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर झोंकी ताकत

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल बुधवार को मतदान होगा। सुबह 7.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। पुलिस की गश्त व निर्वाचन आयोग की पैनी नजर लगी हुई है। वहीं चुनाव लडने् वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी पर पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर दक्षिण के 2 लाख 71 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 253 मुख्य मतदान केन्द्र, और 13 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या पुरूषों की तुलना में ज्यादा है। यहां 1 लाख 37 हजार से अधिक महिला और 1 लाख 33 हजार पुरुष मतदाता हैं।

मतदान केन्द्रों में इस बार प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। मतदाताओं के लिए कुर्सियां और पानी आदि का इंतजाम किया गया है। सभी मतदान दल मंगलवार को मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए। मतदान केन्द्रों को भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। चूंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र में मतदान है,इसलिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को हुजूम रहेगा कि कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाये और मतदान करवायें। इसलिए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के मूड में है प्रशासन और जरा भी चालाकी दिखाई तो सीधे हवालात जाने पड़ सकते हैं।

कांग्रेस और भाजपा ने यहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी कोशिश की है। इस सीट पर विधानसभा चुनाव में 56 फीसदी के आसपास मतदान हुआ था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। होटल और रेस्टॉरेंट में भी मतदान करने वालों के लिए विशेष रूप से छूट का ऐलान किया गया है। यह सुविधा अगले 6 दिन रहेगी।

मतदान दल पहुंचा मतदान केंद्र, फूलों से हुआ स्वागत - रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन के रवाना हुए मतदान दल के मतदान केंद्रों में पहुंचने पर फूलों की माला से स्वागत किया गया। सभी मतदान केंद्रों के कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाया गया। इस दौरान मतदान दलों का उत्साह बढ़ गया और निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन का धन्यवाद जताया। कर्मचारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों में पहुंचने के बाद भव्य स्वागत किया गया। इससे बड़ा गर्व महसूस हुआ।

जनजातीय गौरव दिवसः प्रस्तुति देने कई राज्यों के आदिवासी नर्तक दल पहुँचे

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 14 एवं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। दो दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के आदिवासी नर्तक दल मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर अपने नृत्य की प्रस्तुति देने नर्तक दलों छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, राजस्थान और सिक्किम के आदिवासी नर्तक दल रायपुर पहुंच चुके हैं। अरूणाचल प्रदेश के नर्तक दल आदिलोक नृत्य नाटिका, उत्तराखंड के नर्तक दल झींझी, होली, हन्ना और दिया नृत्य, तेलंगाना के नर्तक दल माथुरी जनजाति नृत्य, राजस्थान के नर्तक दल वालर गरासिया गैर नृत्य और सिक्किम के नृतक दल सुब्बा लोक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देंगे। उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर एवं 15 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान में संध्या 3 बजे से अंतर्राज्यीय लोक नर्तक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ-साथ जनजातीय गौरव से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन तथा जनजातीय जीवन शैली पर चित्रकला का प्रदर्शन भी होगा।

मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल

समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की 6 साल से लंबित मांग 24 घंटे के अंदर हुई पूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री साय की पहल पर समिति कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा 24 घंटे के भीतर पूर्ण करते हुए समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। इसके साथ ही अन्य 2 मांगों के संबंध में शासन स्तर पर अंतर्विभागीय समिति का गठन कर उचित कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय के पहल पर वर्ष 2018 के बाद पहली बार सहकारी समितियों के लगभग 13 हजार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारियों की मांगों पर स्वयं संज्ञान लेकर इनके निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये थे, इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री साय के समक्ष 10 नवम्बर को विभागीय अधिकारियों के साथ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों के शीघ्र निराकरण के संबंध में निर्देश दिये। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा संवेदनशीलता के साथ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों के निराकरण करने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ धान उपार्जन सुगमतापूर्वक किये जाने के निर्देश सभी विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों को दिये गये हैं। धान उपार्जन के दौरान उपार्जन केन्द्रों का सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिये हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा 4 नवम्बर 2024 से की जा रही हड़ताल आज समाप्त घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र साहू ने समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त घोषित करते हुए कहा है कि समस्त समिति कर्मचारी शासन की समस्त योजनाओं का समिति स्तर से क्रियान्वयन किए जाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कर्मचारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसव राजू एस. अन्य अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि

मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में आयुक्त सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन किये जाने के आदेश 11 नवम्बर 2024 को जारी कर दिये गए। इसमें समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों में हर्ष एवं उल्लास व्याप्त है।

खाद्य विभाग द्वारा इस आशय का पत्र भी जारी कर दिया गया है कि धान उपार्जन समाप्त होने के एक माह के अंदर धान का उठाव राइस मिलर्स एवं विपणन संघ द्वारा किया जाएगा, यदि इसके पश्चात् भी उपार्जन केन्द्रों में धान शेष रहता है तो खाद्य विभाग द्वारा सहकारी समितियों को धान की सूखत दिये जाने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाएगा। कर्मचारियों की अन्य मांग के निराकरण के संबंध में खाद्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं विपणन संघ को शामिल करते हुए एक अंर्तविभागीय समिति का गठन किया गया है, जो कर्मचारी संघ की मांग पर विचार कर निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगी।

कर्मचारी अपनी-अपनी समितियों में कार्य में वापस लौटे

सभी कर्मचारी अपनी-अपनी समितियों में कार्य में वापस आ गए हैं तथा 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ हो रही धान खरीदी की समुचित व्यवस्था में लग गए हैं। कर्मचारियों द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि किसानों को धान उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई नही होगी। धान उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक तैयारी 13 नवम्बर 2024 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

प्रदीप उपाध्याय आत्महत्या की जाँच शुरू

कमिश्नर ने 20 तारीख़ तक माँगे साक्ष्य

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे रायपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ शासकीय कर्मचारी प्रदीप उपाध्याय के आत्महत्या मामले की जाँच शुरू कर दी है । संभागायुक्त ने इस संबंध में आम जनों, संस्थाओं के साथ साथ कर्मचारी संघो से भी दस्तावेज, साक्ष्य और गवाही देने तिथि और समय सीमा तय की है । श्री प्रदीप उपाध्याय की आत्महत्या के मामले में संभागायुक्त के समक्ष 13 नवम्बर से 20 नवम्बर 2024 तक साक्ष्य पेश किए जा सकते है साथ ही मामले से जुड़े तथ्यों पर गवाही भी दी जा सकती है। आम जन, संस्था या कर्मचारी संघ प्रदीप उपाध्याय आत्महत्या के बारे में कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य या गवाही कमिश्नर कार्यालय,रायपुर संभाग में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम साढ़े पाँच बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है । ग़ौरतलब है कि रायपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ रहे सहायक ग्रेड-2 प्रदीप उपाध्याय की आत्महत्या के मामले की जाँच के लिए राज्य शासन में संभागायुक्त श्री महादेव कावरे को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है और जाँच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिये गये है ।

दक्षिण की जनता युवा आकाश के पक्ष में मतदान करेगी

रायपुर। दक्षिण उपचुनाव के मतदान के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दक्षिण की जनता बदलाव के लिये मतदान करेगी। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान का आग्रह किया है। कांग्रेस का प्रत्याशी युवा और जुझारू है। कांग्रेस का प्रत्याशी युवा है, उनको व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। इसके विपरीत भाजपा प्रत्याशी पर सांसद रहते हुये निष्क्रियता का तमगा लगा हुआ है। रायपुर की जनता ने सांसद के रूप में सुनील सोनी को अवसर दिया था लेकिन वे जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाये। कांग्रेस ने उनके मुकाबले सक्रिय युवा को मौका दिया है। विधायक के रूप में आकाश शर्मा रायपुर दक्षिण की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। सरकार की असफलता से जनता में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दक्षिण उपचुनाव को लेकर उत्साह है। कांग्रेस का कार्यकर्ता दक्षिण में कांग्रेस का विधायक बनाने को तत्पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य की आम आदमी भाजपा के राज में अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है।

बाघ की मृत्यु की घटना पर मुख्यमंत्री के कड़े तेवर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरिया जिले में बाघ की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव को दिए थे। इन निर्देशों के परिपालन में कोरिया वनमंडल बैकुण्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के रामगढ़ सर्किल के वनरक्षक श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल श्री रामप्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसी तारतम्य में परिक्षेत्राधिकारी सोनहत के वन क्षेत्रपाल श्री विनय कुमार सिंह से टाईगर की मृत्यु के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों से वनों की रक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मुस्तैदी से कर्तव्यों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री कल छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति का करेंगे विमोचन- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 14 नवम्बर को शाम 6.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन करेंगे। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

जनता एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताएगी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता-जनार्दन एक बार फिर भाजपा को इस उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी बना रही है और इसी संकल्प के साथ कल 13 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्र के मतदाता स्वस्फूर्त मतदान करने पहुँचेंगे। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण की जनता से भारी संख्या में मतदान कर भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को रिकॉर्ड जीत दिलाने की अपील करते हुए कहा है कि पिछले पाँच वर्ष प्रदेश की सत्ता पर भी काबिज रहने के बावजूद कांग्रेस ने रायपुर शहर में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी। जनता को बताने के लिए कांग्रेस के पास चूँकि न तो विकास के काम हैं और न ही कोई मुद्दा, इसलिए कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में विरोध की राजनीति करने का शर्मनाक पैंतरा अपनाया। कांग्रेस अपने इन ओछे पैंतरों में कतई कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि सोमवार को रायपुर दक्षिण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निकली जन आशीर्वाद यात्रा जनता-जनार्दन ने जिस तरह उत्साह और उमंग का परिचय देते हुए स्वागत किया.

दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश की जीत सुनिश्चित

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदान को एक दिन शेष है। वरिष्ठ कांग्रेसी अरुण वोरा लगातार सक्रियता से पखवाड़े भर से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री टी एस सिंहदेव , अन्य विधायकों एवं कांग्रेस नेताओं के साथ रैलियां एवं रोड शो के साथ ही वोरा ने घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया एवं वोट देने की अपील की।उनके साथ पूर्व विधायक शैलेष पांडे, विधायक विद्यावती सीदर, रिसाली महापौर हेमा देशमुख, पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, ज्ञानेश शर्मा, आर एन वर्मा, संदीप तिवारी, जयशंकर तिवारी, कमलेश मिश्रा, गोवर्धन शर्मा, अजय मिश्रा और राजकुमार पाली भी निरंतर हर दिन उपस्थित रहते हुए कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। वोरा ने कहा कि प्रदेश की जनता लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के राष्ट्रव्यापी समस्या से ग्रसित होने के साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार की कमजोर प्रशासनिक पकड़, बढ़ते अपराध के ग्राफ आए दिन हो रही गंभीर आपराधिक घटनाओं से त्रस्त है। चारो तरफ भय का माहौल है। सरकार की निरंकुश नीतियों को अंकुश लगाने के लिए रायपुर दक्षिण की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का मन बना लिया है।

महीने भर तक अटेंड नहीं कर पाएंगे क्लास

रैगिंग पर मेडिकल कॉलेज के पांच छात्र निलंबित

रायपुर। रैगिंग के मामले में पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सेकंड ईयर के पांच छात्रों को निलंबित कर दिया गया है. 2023 बैच के पांच छात्रों एक महीने तक कक्षाओं और क्लीनिक पोस्टिंग में शामिल नहीं होंगे. यह कार्रवाई एंटी रैगिंग कमेटी में सुनवाई के बाद हुई है. यह भी पढ़ें = रायपुर दक्षिण विस उप चुनाव = कलेक्टर और एसएसपी ने मतदान दलों को चुनाव सामग्री के साथ किया रवाना›

पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत जिन सेकंड ईयर के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें अंशु जोशी, अक्षत जायसवाल, विकास टंडन, गौरव चंद्र महाली और आयुष गुप्ता शामिल हैं. इस संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यालय अधिष्ठाता की ओर से पत्र जारी किया गया है.

बता दें कि रैगिंग की यह घटना बीते महीने प्रथम वर्ष के जूनियर छात्रों के साथ हुई थी. इसके बाद परिजनों ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) में शिकायत करने के साथ इंटरनेट में भी इस तरह की शिकायतें पोस्ट कर एनएमसी को टैग किया था. परिजनों की शिकायत के बाद कॉलेज में खलबली मच गई थी. विवाद गहराने के बाद आनन-फानन में एंटी-रैगिंग कमेटी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई. एंटी-रैगिंग कमेटी ने शिकायतों की जांच में जूनियर छात्रों के आरोपों को सही पाया, जिसके आधार पर अब निलंबन की कार्रवाई की गई है. कॉलेज डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने बताया कि वार्षिकोत्सव आयोजन में कार्यक्रम को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, जो धीरे-धीरे बढ़ गई. मामला संज्ञान में आते ही तत्काल दोनों पक्षों को समझाया गया था. पुलिस कार्रवाई और कॉलेज से निकाल देना इसके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के सवाल हैं. इसके साथ ही उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी. सूत्रों की मानें तो सीनियर छात्रों ने जूनियरों के साथ बेहद अमानवीय बर्ताव किया था. ऐसी चर्चा है कि करीबन 50 छात्रों के सिर भी मुंडवा दिए गए थे. इतना ही नहीं प्रथम वर्ष के छात्रों का वॉट्सएप ग्रुप बनाकर जूनियर लड़कियों की फोटो मांगी जा रही थी. इसके अलावा सभी छात्रों को बाल एकदम बारीक यानी मुंडवाकर रखने, कॉलेज परिसर में फिट कपड़े न पहनने, सामान्य बैग टांगने, ज्यादा स्टाइलिश जूते न पहनने जैसे तुगलकी फरमान भी थोप दिए गए थे.

चालू खरीफ वर्ष के लिए धान खरीदी व्यवस्था की प्रारंभिक तैयारियां पूर्णः दयालदास बघेल

रायपुर। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंत्री श्री बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने मंत्री श्री बघेल को अवगत कराया कि धान उपार्जन के संबंध में संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जायेगा।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कुषकों की संख्या 27,01,109 है। इस वर्ष 1,35,891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रक्बों का पंजीयन किया गया है। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रक्बे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है। सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बड़े कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 07 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। खरीदी सीजन में लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बड़े कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी।

मंत्री श्री बघेल ने बताया कि धान खरीदी अवधि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के दौरान किसान अपना धान खरीदी केन्द्रों में लाकर समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकते है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.